



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1991/चैत्र 9, 1913
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1991/CHAITRA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India other than
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली 21 फरवरी 1991

का आ 869—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2) नियम, 12 के उप नियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उप नियम (1) के द्वारा पदोन्नतियों का प्रयोग करते हुए और विधि मंत्रालय का आदेश का नि आ 616 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 तारीख 18 फरवरी, 1991 में प्रकाशित किया गया था उस आदेश के विधायी अधिसूचना के रूप में जारी किया गया है। निदेश देते हैं कि—

(1) इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' के पदों की बाबत स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के नियम में स्तम्भ 2, 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

(2) उपर्युक्त अनुसूची के भाग 2 और 3 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' और साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' के पदों की बाबत स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के नियम में स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे और स्तम्भ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग-1—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शामिल अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शामिल जिल्ले वह अधिरोपित कर सकेंगा (नियम 11 में मद संख्याओं के प्रति निर्देश में)	अपील प्राधिकारी	
		प्राधिकारी	शामिल	
1	2	3	4	5
विधि और न्याय मंत्रालय निर्वाचन आयोग का कार्यकारी समूह 'ख' पद (राजपत्रित और अराजपत्रित)	उप निर्वाचित आयुक्त	उप निर्वाचित आयुक्त महोदय निर्वाचित आयोग	सभी (1) से (4) (नव शामिलियां)	मुख्य नियुक्ति आयुक्त/ मुख्य नियुक्ति आयुक्त

भाग 2--साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियाँ जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा कर सकेगा (नियम 11 में मदसंख्याक के प्रति निर्देश से)	अपील प्राधिकारी
	प्राधिकारी	शास्ति	
1	2	3	4
निर्वाचन आयोग का कार्यालय सभी पद	सचिव निर्वाचन आयोग	सचिव निर्वाचन आयोग	सभी उप निर्वाचन आयुक्त

भाग 3--साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियाँ जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा कर सकेगा (नियम 11 में मद संख्याक के प्रति निर्देश से)	अपील प्राधिकारी
	प्राधिकारी	शास्ति	
1	2	3	4
निर्वाचन आयोग का कार्यालय सभी पद	अवर सचिव निर्वाचन आयोग	अवर सचिव निर्वाचन आयोग	सभी उप निर्वाचन आयुक्त

[सं ए-45011/49/90-प्रशासन-1 (विधायी विभाग)]

बाबूलाल, उप सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st February, 1991

S.O. 868.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the orders in the Ministry of Law vide S.R.O. 616 published in the Gazette of India, Part II Section 3 dated the 28th February, 1957, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that—

- (1) In respect of the posts in the General Central Service, Group 'B' specified in column 1 of Part I

of the Schedule to this order, the authorities specified in columns 2, 3 and 5 shall be the Appointing Authority Disciplinary Authority and Appellate Authority respectively, in regard to the penalties specified in column 4 ;

- (2) In respect of the posts in the General Central Service, Group 'C' and the General Central Service, Group 'D' specified in column 1 of part II and part III of the said Schedule, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the Disciplinary Authority and Appellate Authority respectively, in regard to the penalties specified in column 4. —

SCHEDULE

PART I—GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP B

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penenalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE Office of the Election Commission Group 'B' Posts (Gazetted and Non-Gazetted)	Deputy Election Commissioner	Deputy Election Commissioner Secretary, Election Commission	All (i) to (iv) (minor penalties)	Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner.

PART II—GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'C'

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
Office of the Election Commission All posts	Secretary, Election Commission	Secretary, Election Commission	All	Deputy Election Commissioner

PART III—GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP 'D'

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
Office of the Election Commission All posts	Under Secretary, Election Commission	Under Secretary, Election Commission	All	Deputy Election Commissioner

[No. A.45011/49/90-Adm.I(LD)]

BABU LAL, Secy,

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1991

का.भा. 869:—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी.एस. पाटिल, अधिवक्ता गुलबर्गा (कर्नाटक) को भारतीय दंड संहिता (1960 का 45) की धारा 302, धारा 147 और धारा 148 के साथ पठित धारा 120—ख भारतीय दंड संहिता के अधीन मामला सं. आरसी/2/84 ए.सी.यू. (1) सी.बी.आई., एस.पी.ई. नई दिल्ली, राज्य बनाम डोडप्पा पुत्र श्री गुडप्पा, निवासी ग्राम होडबीरानाहल्ली, तालुक चिन्चोली, जिला गुलबर्गा के और अन्य के जो सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश, गुलबर्गा के न्यायालय में लम्बित है, विचारण और अन्य कार्यवाहियों के संचालन के प्रयोजन के लिए तथा भा.व.सं. की धारा 302/149 के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/38/90-ए.पी.डी.-II]

हजारा सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th March 1991

S.O. 869.- In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2) of 1974, the Central Government hereby appoints

Shri D. S. Patil, Advocate Gulbarga (Karnataka) as Special Public Prosecutor for the purpose of conducting the trial and other proceedings of case No. RC 2/84-ACU (I) CBI, SPE, New Delhi, State versus Doddappa son of Shri Gundappa, resident of Village Hodebeeranahalli, Taluk Chincholi, District, Gulbarga and other under section 120-B Indian Penal Code read with Sections 302, 147 and 148 also for Section 302/149 of the Indian Penal Code (45 of 1860), pending in the Court of Sessions or Additional Sessions Judge, Gulbarga.

[No. 225/38/90-AVD-II]

HAZARA SINGH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

ग्रावेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1991

का.भा. 870:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/61/91-सी.शु.-8 तारीख 17-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल हाकिम महादुर, थेरुविन हाउस, चिरायिनकी ब्रील, वरकला पो., एडवा, विश्वनन्दपुरम जिला, केरल को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, त्रिवेन्द्रम में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, केरल, त्रिवेन्द्रम के समक्ष हजरत हो।

[फा.सं. 673/61/91-सी.शु.-8]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDERS

New Delhi, the 20th March, 1991

S.O. 870.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/61/91-CUS. VIII dated 17-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Abdul Hakim Mahadur, Theruvil House, Chirayinkeezhil, Varkala P.O. Edava, Thiruvananthapuram Distt. Kerala be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.C. of Police, Kerala, Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/61/91-CUS-VIII]

का.भा. 871:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से मशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/69/91-सी.शु.-8 तारीख 25-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्रीमति कमल सुरेश रघुनानी उर्फ श्रीमति माया राजकुमार वीपचन्वानी, 203, सिंधी सोसायटी, बेम्बूर, बम्बई-400071; (ii) कमरा नं. 12, बैक नं. 566, श्री.टी. सेक्शन, उल्हास नगर-II, जिला थाने को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरत हो।

[फा सं 673/69/91-सी.शु.-8]

S.O. 871.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/69/91-CUS. VIII dated 25-1-1991 under the said sub-section that Smt. Karnal Suresh Kamanani, Smt. Maya Rajkumar Deepchandani, 203, Sindhi Society, Chembur, Bombay-400071; (ii) Room No 12, Barrack No. 566, O.T. Section, Ulhasnagar-II, Distt. Thane be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing her from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing herself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/69/91-CUS-VIII]

का.भा. 872:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से मशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा सं. 673/70/91 सी.शु.-8 तारीख 25-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री श्रीमति सुमन नागयण बजाज उर्फ कौशल्या एम. गुरार, क्वार्टर नं. 4 सिंधी कॉलोनी, निकट रामगोपाल इन्डस्ट्री, मुलुंड (प.), बम्बई (ii) कमरा नं. 12, बी.के. नं. 26, उल्हास नगर, जिला थाने को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरत हो।

[फा.सं. 673/70/91-सी.शु.-8]

S.O. 872.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/70/91-CUS. VIII dated 25-1-1991 under the said sub-section that Smt. Suman Narayan Bajaj, Smt. Kaushalya M. Gurar, Quarter No. 4, Sindhi Colony, Near Ramgopal Industry, Mulund (W) Bombay; (ii) Room No. 12, B.K. No. 26, Ulhasnagar, District Thane be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing her from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing herself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/70/91-CUS. VIII]

का.भा. 873:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/71/91-सी.शु.-8 तारीख 25-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री इशान चन्द्रा दत्ता, फ्लैट सं. 43-सी, छ: तल, साधना बिल्डिंग, एन. गमालिया रोड, बम्बई; (ii) 34, एलेनबी रोड कोलकाता, (iii) मैसर्स क्रुसडर मर्चेंडाइसिंग कारपोरेशन, 36, मेकर चेम्बर-1, तीसरा तल, नरीमन प्वाइंट, बम्बई, (i) मैसर्स इंडियन गैस एनालाइजर्स, 118, मिटल चेम्बर्स, 228, नरीमन प्वाइंट, बम्बई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/71/91-सी.शु. 8]

S.O. 873.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/71/91-CUS. VIII dated 25-1-1991 under the said sub-section that Shri Ishan Chandra Datta, Flat No. 43-C, 6th Floor, Sadhna Building, N. Gamadia Road, Bombay; (ii) 34, Allenby Road, Calcutta; (iii) M/s. Crusadar Merchandising Corporation, 36, Maker Chamber-VI, 3rd Floor, Nariman Point, Bombay; (iv) M/s. Indian Gas Analyzers, 118, Mitlar Chambers, 228, Nariman Point, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/71/91-CUS-VIII]

का.भा. 874:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/99/90-सी.शु.-VIII तारीख 19-4-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल रज्जाक अब्दुल्ला, 119, हाजी मोहम्मद बिल्डिंग, नय्यद मार्ग, हुंघरी, बम्बई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/99/90-सी.शु.-8]

S.O. 874.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/99/90-CUS. VIII dated 19-4-1990 under the said sub-section that Shri Abdul Razak Abdulla, 119, Haji Mohamed Building, Sayed Marg, Dongri, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/99/90-CUS-VIII]

का.भा. 875:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/163/90-सी.शु.-VIII तारीख 22-6-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री के. कमरुद्दीन बन्द के. पोक्क, (i) कुन्ताय बलायिल पूराय नोवकनपेट्टी, पो. बरीकड, त्रिचूर, जिला (ii) बलायकट पूराय हाउस, ब्रेवी लैंड रोड, श्रीमनायूर रोड, त्रिचूर जिला को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[का.सं. 673/163/90-सी.शु.-8]

S.O. 875.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/163/90-CUS. VIII dated 22-6-1990 under the said sub-section that Shri K. Kamaru-

dheen, son of K Pokku, (u) Kunnath Valappil House, Kowkanapetty, P.O. Vadakkad, Trichur District (ii) Valayakath Purath House, Baby Land Road, Othumanayur Road, Trichur District be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ,

3 Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette

[F. No 673/163/90 CUS-VIII]

का आ. 876 —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का स 673/325/90-सी शु -VIII तारीख 26-9-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ईसाक इस्माइल हाजी राशिद, गाँव एवं तालुका, लुनावाडा, जिला पंच महल, गुजरात को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, गुजरात में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, गुजरात, गांधी नगर के समक्ष हाजिर हो।

[फा सं 673/325/90-सी शु -8]

S.O. 876—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under I No. 673/325/90-CUS-VIII dated 26-9-1990 under the said sub-section that Shri Issak Ismail Haji Rashid, Village and Taluka, Lunawada, District Pancha Mahal, Gujarat be detained and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ;

2 Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ,

3 Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Gujarat, Gandhi Nagar within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette

[F No 673/325/90-CUS-VIII]

या आ 177 —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया

गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का स 673/328/90-सी शु -VIII तारीख 22-10-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल मथन काजिया बन्धु श्री हुसैन माहिब काजिया (i) फरान मेन रोड, भटकल, (ii), न 11 पाचवा मेन एम के गार्डन, बंगलूर-46, (iii) न 53, पहला तल, पाचवा कास, मरप्पा गार्डन, जे.सी नगर, बंगलूर 6 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बंगलूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उस देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बंगलूर के समक्ष हाजिर हो।

[फा सं 673/328/90-सी शु -8]

S.O. 877.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F No 673/328/90 CUS, VIII dated 22-10-1990 under the said sub-section that Shri Abdul Mathen Kazia, son of Shri Hussain Sahib Kazia (i) Faran, Main Road, Bhatkal, (ii) No 11, 5th Main, S K. Garden, Bangalore-46, (iii) No. 53, 1 Floor, 5th Cross Marappa Garden, I. C. Nagar, Bangalore 6 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bangalore with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange ,

2 Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3 Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette

[F No 673/328/90-CUS-VIII]

का आ 878 —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा और संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का स 673/329/90-सी शु -8 तारीख 22-10-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद युसुफ काजिया बन्धु श्री माहिब काजिया (i) फरान मेन रोड, भटकल, (ii), न 11, पाचवा मेन एम के गार्डन, बंगलूर-46, (iii) न 53, पहला तल, पाचवा कास, मरप्पा गार्डन, जे.सी नगर, बंगलूर-46 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बंगलूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बंगलूर के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/329/90-सी.शु.-8]

S.O. 878.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/329/90-CUS. VIII dated 22-10-1990 under the said sub-section that Shri Mohammed Yousuf Kazia, son of Hussain Sahib Kazia; (i) Faran, Main Road, Bhatkal; (ii) No 11, 5th Main, S. K. Garden, Bangalore-46; (iii) No. 53, 1 Floor, 5th Cross, Marappa Garden, J. C. Nagar, Bangalore-46 detained and kept in custody in the Central Prison, Bangalore with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing herself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/329/90-CUS-VIII]

का.आ. 879:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/334/90-सी.शु.-8 तारीख 8-10-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री प्रकाश नटवरलाल बरोत, एमनेन्ड एपार्टमेंट्स, वु. सं. 8, बकोला मार्केट रोड बकोला मार्केट, शांताकुल (पू.), बम्बई-400055 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने में रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/334/90-सी.शु.-8]

S.O. 879.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/334/90-CUS. VIII dated 8-10-1990 under the said sub-section that Shri Prakash Natwarlal Barot, Emralde Apartments, Shop No 8, Vakola Market Road, Vakola Market, Santacruz (E), Bombay-400055 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/334/90-CUS-VIII]

का.आ. 880:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/344/90-सी.शु.-8 तारीख 22-10-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मुस्ताक अब्दुल रजक साईकिल वाला, हारूर कोटिज, ब्लॉक नं. 5, सी.एस.टी. रोड, कुर्ला (पूर्वी), बम्बई-100070, को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने में रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हजरि हो।

[फा.सं. 673/344/90-सी.शु.-8]

S.O. 880.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/344/90-CUS. VIII dated 22-10-1990 under the said sub-section that Shri Mustaq Abdul Razzak Cyclewala, Haroor Cottage, Block No. 5, C.S.T. Road, Kurla (East), Bombay-400070 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/344/90-CUS-VIII]

का.आ. 881:—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/364/90-सी.शु.-8 तारीख 8-11-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सैयद फारूक अली

उक्त आसिफ, नल्ल सैयद अजीज़ अली, नं. 10-2-348/10 आसिफ नगर, बैंक कालोनी, हैदराबाद को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, हैदराबाद में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, हैदराबाद के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/364/90-सी. शु.-8]

S.O. 881.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/371/90-CUS.VIII dated 8-11-1990 under the said sub-section that Shri Syed Farooq Ali Asif, son of Syed Azeez Ali, No. 10-2-348/10, Asif Nagar, Bank Colony, Hyderabad be detained and kept in custody in the Central Prison, Hyderabad with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Hyderabad within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/364/90-CUS-VIII]

का. आ. 882.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/371/90-सी. शु.-8 तारीख 13-11-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मोहम्मद इस्माइल शबन्दरी वल्द श्री अहमद शबन्दरी, (i) 729/26, भूमि तल, मुनिस्वारप्पा ब्लॉक, नागप्पा-स्ट्रीट, पेलेस गेट हाइली, बंगलूर-3, (ii) 46, मुस्लिम स्ट्रीट, भटकल को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बंगलूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बंगलूर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/371/90-सी. शु.-8]

S.O. 882.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/371/90-CUS.VIII dated 13-11-1990 under the said sub-section that Shri Mohammed Ismail Shabandri, son of Ahmed Shabandri, (i) 729/26 Ground Floor Muniswarappa Block Nagappa Street, Palace Guttahally Bangalore-3; (ii) 46, Muslim Street, Bhatkal be detained and kept in custody in the Central Prison Bangalore with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bangalore within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F No. 673/371/90-CUS-VIII]

का. आ. 883.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/388/90-सी. शु.-8 तारीख 26-11-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ए. ए. हजा भैदीन वल्द श्री ए. एम. अन्वुल बहाव, (i) नं. 7-सी, गांधी नगर, कुम्भाकोनम; (ii) 1-65, नूरिया स्ट्रीट (रहमानिया स्ट्रीट), अथिकडाई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे देश की विदेशी मुद्रा स्रोतों की अभिवृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी कार्य में लगने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/388/90-सी. शु.-8]

कुलदीप सिंह, अवर सचिव

S.O. 883.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/388/90 CUS VIII dated 26-11-1990 under the said sub-section directing that Shri A. A. Haja Majidun, son of Shri A. M. Abdul Wahab, (i) No. 7-C, Gandhi Nagar, Kumbakonam, (ii) 1-65, Nooriya Street (Rahumaniva Street) Athikadai be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D. G. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/388/90 CUS-VIII]

KU DIP SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1991

का. ग्रा. 884 भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/17/91-मी. शु.-8 तारीख 14-1-91 यह निर्देश देने हुए जारी किया था कि श्री कालुमल मेहर चन्दानी, बरक न. 543, उल्हास नगर, थाने-421009 (महाराष्ट्र) को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/17/91 - मी. शु.-8]

ORDERS

New Delhi, the 1st March, 1991

S.O. 884.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/17/91-CUS VIII dated 14-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Kalumal Mehar Chhandani, Barrack No. 543, Ulhasnagar, Thane-421009 (Maharashtra) be detained and kept in custody in the Central

Prison, Bombay with a view to preventing him from Smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/17 91-CUS-VIII]

का. ग्रा. 885.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/18/91-मी. शु.-8 तारीख 14-1-91 यह निर्देश देने हुए जारी किया था कि श्री रशीद अलाउद्दीन, 644, भारत नगर, बान्द्रा, बम्बई-51 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/18/91 - मी. शु.-8]

S.O. 885.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/18/91-CUS.VIII dated 14-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Rasheed Allaud-Gin, 644, Bharatnagar, Bandra, Bombay-51, be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from Smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3 Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette

[F. No. 673/18/91-CUS-VIII]

का. आ. 886—भारत के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/25/91-सी. शु. 8 तारीख 22-1-1991 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री अब्दुल रौफ मोहम्मद उमर मनिअर, 27, ऐमबाई विल्डिंग, मकान नं. 71, तीसरा तल, मेमोनवाला रोड, बम्बई-4000 003 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने में रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/25/91-सी. शु. 8]

S.O. 886.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/25/91-CUS-VIII dated 22-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Abdul Rauf Mohamad Umer Maniar, 27, Aishabai Bldg. R. No. 71, 3rd Floor, Memonwala Road, Bombay-400 003 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/25/91 CUS-VIII]

का. आ. 887.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/27/91—सी. शु.-8 तारीख 14-1-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री राजकुमार जेठनन्द मेहानी, भोलेनाथ कालोनी, कमरा नं. 35, उल्हास नगर, थाने को निरुद्ध कर लिया

जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने में रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/27/91-सी. शु.-8]

S.O. 887.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/27/91 CUS-VIII dated 14-1-1991 under the said sub-section directing that Shri Rajkumar Jethanand Mewani, Bholenath Colony Quarter No. 35, Ulhasnagar, Thane be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/27/91-CUS-VIII]

का. आ. 888.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का. सं. 673/28/91—सी. शु.-8 तारीख 22-1-1991 यह निदेश देने हुए जारी किया था कि श्री कमल रामन, 113, जवाहर नगर, कुर्ली, बम्बई-52 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने में रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/28/91-सी. शु.-8]

जे. एन. माठुली, प्रवर सचिव

S.O. 888.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/28/91-CUS-VIII dated 17-3-1989 under the said sub-section directing that Shri Kamal Raman, 113, Jawahar Nagar, Kurla, Bombay-52 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/28/91-CUS-VIII]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1991

का. आ. 889.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/202/89—सी. गु.-8 तारीख 17-5-89 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि धीरूभाई सोमाभाई पटेल बन्द श्री सोमाभाई ठेकामाई पटेल, संधुवन बिल्डिंग, चौथा तल, बम्बई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/202/89—सी. गु.-8]

ORDERS

New Delhi, the 21st March, 1991

S.O. 889.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/202/89-CUS-VIII dated 17-3-1989 under the said sub-section directing that Shri Dhirubhai Somabhai Patel, son of Somabhai Dhakabhai Patel, Sandhurst Buildings, 4th Floor, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication in this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/202/89-CUS-VIII]

का. आ. 890.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/191/89—सी. गु.-8 तारीख 16-5-1989 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री कु. आर. विमला देवी सुपुत्री राजाबुराई, सी/ओ मरस्वती लाज, मेन गार्ड गेट, त्रिची को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, त्रिची में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/191/89—सी. गु.-8]

S.O. 890.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/191/89-CUS-VIII dated 16-5-1989 under the said sub-section directing that Miss R. Vimla Devi, D/o. Rajadurai, C/o. Saraswathi Lodge, Main Guard Gate, Trichy be detained and kept in custody in the Central Prison, Trichy with a view to preventing her from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D. C. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/191/89-CUS-VIII]

का. आ. 891.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त

उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/338/90—सी. शु.-8 तारीख 9-10-1990 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री आर. फ्रेडिस बल्द रायर नादर, डोर में 9/III स्ट्रीट, टूवोपुरम, टूटोकोरिन, तमिलनाडु को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, पलायमकोटाई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि सामान की तस्करी करने में रोक जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3 अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, के समक्ष हजरि हो।

[फा. सं. 673/338/90—सी. शु.-VIII]

रा. देसीकन, अवर सचिव

S.O. 891.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/338/90-CUS.VIII dated 9-10-1990 under the said sub-section directing that Shri R. Francis, son of Rayar Nadar, Door No. 9, VIII Street, Toovipuram, Tuticorin, Tamilnadu be detained and kept in custody in the Central Prison Palayamkottai with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D. C. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

IF. No. 673/338/90-CUS.VIII]

R. DESIKAN, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1990

आयकर

का आ. 832—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "11.5 प्रतिशत इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन बंधपत्र, 2010 (सत्तावनवीं श्रृंखला)" को एनद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है;

वर्षों कि उक्त परन्तुक के अन्तर्गत लाभ इस प्रकार के बन्धपत्रों के अन्तर्गत के मापने में पूर्णतः अथवा विनश्वर द्वारा केवल तभी अनुमत्य होगा यदि अन्तर्गति इस प्रकार के अन्तरण में 60 दिन की अवधि के भीतर इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आई.एफ.सी.आई. बन्धपत्रों को जारी करने तथा उनके प्रबंध के लिए प्रभारी प्रबंधक) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करेगा।

[सं. 8847/फा.स. 273/206/90-आ. कर (व)]

राजेश चन्द्र, अवर सचिव

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi the 31st December, 1990

INCOME-TAX

S.O. 892.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specified the "11.5 per cent Industrial Finance Corporation Bonds, 2010 (Fifty Seventh Series)" issued by the Industrial Finance Corporation of India, New Delhi, for the purposes of the said clause;

Provided that the benefit under the said proviso shall be admissible in the case of transfer of such bonds, by endorsement of delivery only if the transferee informs the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India (Managers incharge for the issue and management of IFCI bonds) by registered post within a period of sixty days of such transfer.

[No 8847/F. No. 275/206/90-IT(B)]

RAJESH CHANDER, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1991

का.सा. 893—पूजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29वा) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 9 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना गड्या का.सा. क्रमांक 1112 का अधिश्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा पूजी निर्गम नियंत्रण मन्त्रालय सचिवालय का पुनर्गठन इस प्रकार करती है।

1. श्री मनु शर्मा	अध्यक्ष
2. श्री मुरली देवरा,	सदस्य
समद सदस्य	
3. डा. ए. वसन्ती. राज	सदस्य
4. डा. एम.ए. रौ	सदस्य
5. श्री एस.के. विश्वा	सदस्य

2 सलाहकार समिति के कार्यकाल की अवधि इस अधिसूचना के जारी किए जाने का तारीख से दो वर्ष की होगी।

[सदस्य एम 8(1)-सी सी आई (11)/90]

कमल पण्डे भारत सरकार के संयुक्त सचिव और

पूँजी निर्गम नियंत्रक

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

New Delhi, the 22nd February, 1991

S.O. 893.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Economic Affairs S.O. No. 1112 dated the 9th April, 1988, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee on the Capital Issues Control as under :—

1. Shri Manu Shroff	Chairman
2. Shri Murli Deora, M.P.	Member
3. Dr. A. Besant C. Raj	Member
4. Dr. S. A. Dave	Member
5. Shri S. K. Birla	Member

2. The Advisory Committee shall have a tenure of two years with effect from the date of this notification.

[No. S.8(1)-CCI(ii)/90]

KAMAL PANDE Jt. Secy. to the Govt. of India & Controller of Capital Issues

वार्णिज्य मन्त्रालय

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1991

का.आ. 894.—निर्यात (स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I तथा II), अकार्बनिक रसायनों, अकार्बनिक वर्णकों, कपड़े धोने का साबुन, उष्मसह ईंटों, खर बैल्टिंग, खर नम्यनालों, खर बैल्टों, खर के दम्पानों, खर की गर्म पानी की बोतलों, खर की बर्फ की थैलियों तथा कार्बनिक रसायनों के पान लदान पूर्व निरीक्षण के लिए मैसर्स इटालैब प्राइवेट लिमिटेड को जिनका पंजीकृत कार्यालय महार हाऊस, छठी मंजिल, 15 कावामजी पटेल स्ट्रीट, पोस्ट बॉक्स नं. 1832, बम्बई 400001 में है निरीक्षण अधिकरण के रूप में मान्यता दी थी।

और ऐसा देखा गया है कि मैसर्स इटालैब प्राइवेट लिमिटेड बम्बई ने भारत सरकार द्वारा निहित प्राधिकारों का घोर दुरुपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किए बिना कि परेषण सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मानकों के अनुरूप है, प्राप्ति-पत्र पंक्ति के लिए 21-7-90 की निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया है।

और मैसर्स इटालैब प्राइवेट लिमिटेड बम्बई को इस मामले में अधिकृत करने के लिए उचित अवसर दिया गया।

अतः अतः, निर्यात (स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I तथा II) अकार्बनिक रसायनों, अकार्बनिक वर्णकों, कपड़े धोने का साबुन, उष्मसह ईंटों, खर बैल्टिंग, खर नम्यनालों, खर बैल्टों, खर के दम्पानों, खर की गर्म पानी की बोतलों, खर की बर्फ की थैलियों तथा कार्बनिक रसायनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स इटालैब प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई का दी गई मान्यता वापिस लेती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फाइल नं. 3/52/90-ई आई एण्ड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th March, 1991

S.O. 894.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) had recognised M/s. Italab Private Limited having their registered office at Mehar House, 6th floor, 15 Cawasji Patel Street, Post Box No. 1832, Bombay-400001 as an inspection agency for pre-shipment inspection of Minerals and Ores (Group I and II), Inorganic Chemicals, Inorganic Pigments, Laundry Soap, Refractory Bricks, Rubber Beltings, Rubber Hoses, Rubber Belts, Rubber Gloves, Rubber Hot Water Bottles, Rubber Ice Bags and Organic Chemicals.

And whereas it was observed that in gross abuse of authority vested on them by the Government M/s. Italab Pvt. Limited, Bombay had issued inspection certificate dated 21-7-90 for Oxalic Acid without ensuring that the said consignment conform to the minimum standards as notified by the Government.

And whereas reasonable opportunity was given to M/s. Italab Pvt Ltd, Bombay to make representation in the matter:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, the Central Government hereby withdraws recognition granted to M/s. Italab Pvt. Ltd., Bombay for inspection of Minerals and Ores (Group-I and II), Inorganic Chemicals, Inorganic Pigments, Laundry Soap, Refractory Bricks, Rubber Beltings, Rubber Hoses, Rubber Belts, Rubber Gloves, Rubber Hot Water Bottle, Rubber Ice Bags and Organic Chemicals, prior to export.

This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/52/90-EI&IPI]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1991

का.आ. 895.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात (स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के उपरान्त में विनिर्दिष्ट पेंट तथा रंगरूढ़ उत्पादों के संबंध में भारतीय मानक व्यूरो प्रमाणन चिन्ह

को मान्यता देने की एक प्रस्थापना, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.या. 1085, तारीख 21 अप्रैल, 1990 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 28 अप्रैल, 1990 में प्रकाशित किया था।

और ऐ.प. सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंटिंग्स बिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6-6-1990 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, और उक्त प्रस्थापना के मद्देन से जनता में प्राप्त आश्रयों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, नियति (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपावध में विनिर्दिष्ट पेंट तथा संबद्ध उत्पादों की बाबत यह दिखाने के प्रयोजन के लिए जहां उक्त पेंट तथा संबद्ध उत्पादों के डिब्बों या पैकेजों पर ऐसा चिह्न लगा या लिपिका हो वहां उस के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन उनको लागू मानक विनिर्देशों के प्रत्या है, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न को मान्यता देती है।

उपावध

भाग 1

1. सिलिस्ट इनेमल,
2. उष्मारोधी वार्निश, (वायु, ग्लूकन बिटुमेन प्रकार के),
3. सिलिस्ट वार्निश, परिमज्जक (साधारण प्रयोजन),
4. इमल्शन पेंट (प्लास्टिक ऐकिलिक इमल्शन),

भाग 2

1. सभी प्रकार के तैयार मिश्रित पेंट तथा इनेमल जिनके अन्तर्गत सिलिस्ट इनेमल के सिवाय प्रथमर प्रकार अवलेपक तथा परिमज्जक हैं।
2. सिलिस्ट वार्निश, परिमज्जक (साधारण प्रयोजन) तथा उष्मारोधी वार्निश (वायु ग्लूकन बिटुमेन के) प्रकार के सिवाय सभी प्रकार के वार्निश (प्राकृतिक रेजिन या सिलिस्ट रेजिन या दोनों से निर्मित)।
3. प्लास्टिक तथा ऐकिलिक के सिवाय सभी प्रकार के इमल्शन पेंट।
4. नाइट्रोसेलुलोज लेकर, स्क्वॉल या वर्गीकृत, जिनके अन्तर्गत प्रथम या प्रथम हैं।
5. मिश्रित पेंट तथा पेस्ट डिस्टेंपर।
6. ग्लूक डिस्टेंपर, रंगीन चूना तथा रंगीन सीमेंट।
7. सीमेंट पेंट।

8. पेंट बिल्लक।

9. पेंट के लिए सिलिस्ट रेजिन।

10. पेंट के लिए संसाधित तेल और पेंट के लिए ग्लूकन या अशुद्धित तेल,

11. बिटुमेनी विलेपन,

12. ग्लूमिनियम पेस्ट।

[फाइल सं. 6(5) 85-ई आई एण्ड ई पी]

ए.के. चौधरी, निदेशक

New Delhi, the 13th March, 1991

S.O. 895.—Whereas in exercise of powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government published a proposal to recognise the Bureau of Indian Standard Certificate Mark in relation to Paints and Allied Products as specified in the Annexure to this notification as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 28th April, 1990 under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1085, dated the 21st April, 1990.

And whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 6-6-90.

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Bureau of Indian Standards Certification Marks with respect to Paints and Allied Products specified in the Annexure for the purpose of denoting that where the cartons or package containing the said paints and allied products are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard Specifications applicable thereto under clause (c) of section 6 of the said Act.

ANNEXURE

PART-I

1. Synthetic enamels.
2. Insulating varnishes (air drying, bitumen type).
3. Synthetic varnishes, finishing (General purpose).
4. Emulsion paints, (plastic/acrylic emulsion).

PART-II

1. Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers under-coating and finishing except synthetic enamels.
2. Varnishes of all types (prepared from natural resin or synthetic resins or both), except synthetic varnishes finishing (general purpose) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
3. Emulsion paints of all types, except plastic and acrylic.
4. Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented, including filler, primers or surfacers.
5. Paste paints and paste distempers.

6. Dry distempers, lime colours and cement colours.
7. Cement paints
8. Thinners for paints.
9. Synthetic resin for paints
10. Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints.
11. Bitumenous coatings
12. Aluminium paste.

[File No. 6(5)/85-EI&EP]

A. K. CHAUDHURI, Director

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1991

का.आ. 896.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्यालयों/कार्यालयों को जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है —

1. केन्द्रीय विद्यालय,
बीरपुर, देहरादून,
देहरादून कैंट-248003
2. केन्द्रीय विद्यालय,
सिलसुर,
कछार (असम)
3. केन्द्रीय विद्यालय,
वायुसेना शिबिर, बेगमपेट,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
4. केन्द्रीय विद्यालय,
मोहिया नगर, फकाडबाग,
पटना-800020
5. केन्द्रीय विद्यालय,
वायुसेना स्टेशन,
चान्दीनगर (मेरठ)
6. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1,
आयु निर्माणी, खमरिया,
जबलपुर-482005
7. केन्द्रीय विद्यालय,
गोमती नगर,
लखनऊ
8. केन्द्रीय विद्यालय,
आई.बी.आर.आई.,
भुक्तेश्वर (नैनीताल)
9. केन्द्रीय विद्यालय,
जोगीमठ (उ.प्र.)

10. केन्द्रीय विद्यालय,
रायबाबा, देहरादून
11. केन्द्रीय विद्यालय,
मनकापुर आ. दो आई.,
गोण्डा (उ.प्र.)
12. केन्द्रीय विद्यालय,
लैंग हाउस (गढ़वाल)
13. केन्द्रीय विद्यालय,
उत्तर बागो (नैनीताल)
उत्तर प्रदेश
14. केन्द्रीय विद्यालय,
भारत निवृत्त सीमा पुलिस परिसर,
शिवपुरी-473534 (म.प्र.)
15. केन्द्रीय विद्यालय,
डी.जी.पी.पी.
(रा.ता.वि.नि.)
तमनीवाली तोगवा (पश्चिम)
495450 जिला-बिलासपुर
(मध्य प्रदेश)
16. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1,
अमरापुर,
बानपुर (उ.प्र.)
17. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1
एन.एफ.एल. टाउनशिप
भटिन्डा (पंजाब)
18. केन्द्रीय विद्यालय,
पेपर नगर तुली,
नागालैण्ड
19. केन्द्रीय विद्यालय,
आ.नि.आरवा-412501
(महाराष्ट्र)
20. केन्द्रीय विद्यालय,
गुन्तकल (आन्ध्र प्रदेश)
21. केन्द्रीय विद्यालय
आबुआ,
पो.आबुआ एयरफील्ड,
जिला डिब्रुगढ़ (असम)
22. केन्द्रीय विद्यालय
वायुसेना स्थल बडसर
वाधा कलोल (गुजरात)
23. केन्द्रीय विद्यालय,
वायुसेना मकरपुरा,
बड़ौदा (गुजरात)
24. केन्द्रीय विद्यालय
डी.पी.पी. शोकारा थर्मल,
जिला गिरिडीह (बिहार) 829107

25. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1,
बडीपट्ट क्षेत्र,
पोस्ट 20-31,
बडीपट्ट
26. केन्द्रीय विद्यालय,
सी.ओ.डी., बरनपुर
27. केन्द्रीय विद्यालय,
नेता नगर-150221
28. केन्द्रीय विद्यालय,
सेन्ट्रल कोल फील्डम (वि.)
कारो वि.पे,
पो. ग्रा. सन्डे बाजार,
जिला गिरिडीह-829127
29. केन्द्रीय विद्यालय,
बोना, जिला सागर,
म.प्र.
30. केन्द्रीय विद्यालय,
फिरोट, बिकानेरवादा,
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
31. केन्द्रीय विद्यालय,
ग्राम निमाणी,
ग्रावामीय क्षेत्र,
सुमावन (महाराष्ट्र)
32. केन्द्रीय विद्यालय,
कृष्ण नगर, पो. आ. बहादुरपुर,
बरेल्लान (प. यगाल)
33. केन्द्रीय विद्यालय,
एच.पी.सी. कागजवाड़ा,
जागी रोड (असम)
34. केन्द्रीय विद्यालय नं. 4,
एलनबाई लाईनज,
अम्बाला छावनी-133001
35. केन्द्रीय विद्यालय नं. 2,
अमरपुर, कानपुर (उ.प्र.)
2. Kendriya Vidyalaya,
Silchar, Cachar (Assam).
3. Kendriya Vidyalaya,
Air Force Station,
Begumpet, Hyderabad, (A.P.).
4. Kendriya Vidyalaya,
Lohianagar, Kankarbagh,
Patna-800029.
5. Kendriya Vidyalaya,
Air Force Station,
Chandinagar, Meerut.
6. Kendriya Vidyalaya No. 1,
Central Ordnance Depot,
Khamria, Jabalpur-482005.
7. Kendriya Vidyalaya,
Gomtinagar,
Lucknow.
8. Kendriya Vidyalaya,
I.V.R.I., Mukteshwar,
(Nainital)
9. Kendriya Vidyalaya,
Joshimath, (U.P.).
10. Kendriya Vidyalaya,
Raiwala, Dehradun.
11. Kendriya Vidyalaya,
Mankapur, I.T.I.
Gonda, (U.P.).
12. Kendriya Vidyalaya,
Lance-Down, (Garhwal)
13. Kendriya Vidyalaya,
Uttar Kashi, (Nainital),
Uttar Pradesh.
14. Kendriya Vidyalaya,
I.T.B.P. Complex,
Shivpuri-473534, (M.P.).
15. Kendriya Vidyalaya,
B.G.P.P. Jamniwali,
Korva (West)-495450,
Distt. Bilaspur, (M.P.).
16. Kendriya Vidyalaya No. 1,
Armapur, Kanpur, (U.P.).
17. Kendriya Vidyalaya, No. 2,
N.F.L. Township,
Bhatinda, (Punjab).
18. Kendriya Vidyalaya,
Paper Nagar Tuli,
Nagaland.
19. Kendriya Vidyalaya,
O.F. Chanda-442501,
(Maharashtra).
20. Kendriya Vidyalaya,
Guntkal, (A.P.).
21. Kendriya Vidyalaya,
Chabua,
P. Chabua Air Field,
Distt. Dibrugarh, (Assam).
22. Kendriya Vidyalaya,
Air Force Station, Vadsar,
Via Kalol, (Gujarat).
23. Kendriya Vidyalaya,
Air Force Makarpura,
Baroda, (Gujarat).
24. Kendriya Vidyalaya,
D.V.P. Bokaro Thermal,
Distt. Giridih, (Bihar)-829107.
25. Kendriya Vidyalaya,
Chandigarh Region,
Sector-20-D,

[म. ई. -11011/4/91-ग्रा. भा. ए.०]

रमेश कुमार आंगिरम, निदेशक (रा.भा.०)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 14th March, 1991

S.O. 896.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Language, (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Vidyalayas/Offices of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development, where more than 80 per cent staff has acquired working knowledge of Hindi:—

1. Kendriya Vidyalaya,
Birpur,
Dehradun Cantt.-248003

- Chandigarh.
26. Kendriya Vidyalaya,
C.O.D., Jabalpur.
27. Kendriya Vidyalaya,
Nepa Nagar-450221.
28. Kendriya Vidyalaya,
Central Coal Fields (Ltd.),
Karo,
29. Kendriya Vidyalaya,
Veena, Distt. Sagar,
Madhya Pradesh.
30. Kendriya Vidyalaya,
Pekot Sikandrabad,
Hyderabad, (M.P.).
31. Kendriya Vidyalaya,
Ordnance Depot,
Residential Area,
Bhusawal, (Maharashtra).
32. Kendriya Vidyalaya,
Krishan Nagar, P.O. Bahadurpur,
Burdwan, (W.B.).
33. Kendriya Vidyalaya,
H.P.C. Kaganj Nagar,
Jnagi Road, (Assam).
34. Kendriya Vidyalaya, No. 4,
Alanvy Lines,
Ambala Cantt.-133001.
35. Kendriya Vidyalaya, No. 2,
Armapur, Kanpur, (U.P.).

[No. E-11011/4/91-OLU]

R. K. ANGERAS, Director (OL)

उर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च 1991

का. आ. 877— केन्द्रीय सरकार 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के द्वारा प्रवृत्त रखा गया कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 और 4 के अनुसरण में भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1255 (अ) तारीख 30 दिसम्बर, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में

- (क) "बैकुण्ठपुर" क्षेत्र के सामने कोलियरी शीर्ष के अन्त में प्रविष्टि "दुग्दा बिबूत खान" अन्तःस्थापित की जाएगी।
- (ख) "चिरीमिरी" क्षेत्र के सामने कोलियरी शीर्ष के नीचे अन्त में प्रविष्टि "बोरबेस्ला" अन्तःस्थापित की जाएगी।
- (ग) "सोहागपुर" क्षेत्र के सामने कोलियरी शीर्ष के नीचे अन्त में प्रविष्टि "विवेकनगर इनक्वाईन, बंगवार खान, अमनाई बिबूत खान" अन्तःस्थापित की जाएगी ;

(घ) "कास्ता" क्षेत्र और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्षेत्र और कोलियरी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"जोहिला" पिनोरा खान सं. 1" और

(इ) "सोहागपुर" क्षेत्र के सामने भारत के राजपत्र, तारीख 29 सितम्बर, 1990 में प्रकाशित का. आ. सं. 2547 तारीख 10 सितम्बर, 1990 द्वारा अन्तःस्थापित "क्षेत्र" और "कोलियरी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 28012/6/89-सी ए]

बी. के. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 12th March, 1991

S.O. 897.—In pursuance of clause 3 and clause 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1255(E), dated the 30th December, 1988, namely:—

In the annexure to the said notification,—

- (a) against the area BAIKUNTHPUR under the heading colliery, the entry "Dugda Open Cast Mines" shall be inserted at the end,
- (b) against the area CHIRIMIRI under the heading colliery, the entry "Dugha Open Cast Mines" shall at the end,
- (c) against the area SOHAGPUR under the heading colliery the entries "Viveknagar incline Bangwar Mine Amlai Open Cast Mine" shall be inserted at the end,
- (d) after the area KASTA and entry relating thereto, the following area and colliery shall be inserted, namely: "JOHILA Pinoura Mine No. 1", and
- (e) against the area Sohagpur the words "Area" and "Colliery" inserted vide notification No. S.O. 2547 dated 10th September, 1990 published in the Gazette of India, dated 29th September, 1990 shall be omitted.

[F. No. 28012/6/89-CA]

B. K. SINGH, Addl. Secy.

FOOT NOTE.—The original notification was issued vide No. S.O. 1255(E), dated 30th December, 1988 and published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 30th December, 1988 and Subsequently amended vide No. S.O. No. 2547 dated 10th September, 1990 and published in the Gazette of India, dated 29th September, 1990.

परमाणु उर्जा विभाग

बम्बई, 18 फरवरी, 1991

का. आ. 898—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिकारियों को बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार परमाणु उर्जा विभाग के विभाग

14 अगस्त, 1389 के एस. ओ. स. 2365 की अधि-सूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पहले की गई बातों अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी के समकक्ष अधिकारियों के रूप में, नियुक्त करती

है। ये अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी होंगे, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करंगे और उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसर के संबंध में अपने सम्बद्ध क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन, सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कार्य करेगे।

सारणी

क्रम सं. अधिकारी का पदनाम

सार्वजनिक परिसर की श्रेणी और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं

1. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर)/प्रबंधक (कार्मिक), तारापुर परमाणु बिजली घर पोस्ट आफिस तारापुर, जिला थाणे-401504 (महाराष्ट्र)
2. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर)/प्रबंधक (कार्मिक) मद्रास परमाणु बिजली घर, कलपक्कम-603102, जिला चिगलपट्टु, तमिलनाडु
3. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर)/प्रबंधक (कार्मिक), राजस्थान परमाणु बिजली घर, पोस्ट आफिस अणुशक्ति बाया कोटा राजस्थान-323303
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर)/प्रबंधक (कार्मिक), नरोरा परमाणु बिजली परियोजना पोस्ट आफिस नरोरा बाया दिबई, मुंबई, उत्तर प्रदेश-202397
5. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर) प्रबंधक (कार्मिक), ककरापार परमाणु बिजली परियोजना, ग्राम मोतीचर, मांडवी तालुका, जिला मुरम, गुजरात
6. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर)/प्रबंधक (कार्मिक), राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना 3 एवं 4, पोस्ट आफिस अणुशक्ति बाया कोटा, राजस्थान-323303
7. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर) प्रबंधक (कार्मिक), काइगा परमाणु बिजली परियोजना, 977 रामकुपा आश्रम रोड, काइगा जिला उत्तर कांडा, कर्नाटक-581301
8. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पी एण्ड आई आर) प्रबंधक (कार्मिक), रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग कार्यालय कार्मलेक्स, बिक्रम मारासाई भवन, अणुशक्ति नगर, बम्बई-400094

पालपर एवं दहाणु तालुका, जिला थाणे, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजली घर में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

कलपक्कम जिला चिगलपट्टु तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजली घर में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

राजस्थाना खेरली (अणुशक्ति), बिजम नगर तहसील बेगुन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भाभा नगर में राजस्थान परमाणु बिजली घर में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

पोस्ट आफिस नरोरा बाया दिबई, जिला मुंबई, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु बिजली परियोजना में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

ग्राम मोतीचर, नाभीचर एवं मांडवी तालुका में राजबाड़ा तथा ग्राम ऊहवामाला, वयादा तालुका जिला सूरत, गुजरात में ककरापार परमाणु बिजली परियोजना में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

राजस्थाना, खेरली (अणुशक्ति) बिजम नगर, तहसील बेगुन जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में भाभा नगर में राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना 3 एवं 4 में, रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

ग्राम मल्लपुर, काइगा, कर्नाटक के उत्तर कांडा जिले में काइगा में काइगा परमाणु बिजली परियोजना में रूक्मिलय पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

रूक्मिलय पावर कारपोरेशन के मुख्यालय बम्बई, भारत में बिभिन्न स्थानों में स्थित इसके संपर्क कार्यालय, गुण बिजगा 1 कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय आदि में इसकी प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणी और अधिकार की स्था सय सीमाएं
9.	मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पो एण्ड आर्वाइ आर) प्रबंधक (कार्मिक) राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना 5 से 8, पोस्ट आफिस अनुशक्ति बाया कोटा, राजस्थान-323 103	रावत भाटा खेरवी (अनुशक्ति विक्रम नगर, तहसील बंगुन जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से भाभा नगर में राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना 5 से 8 में स्थूलतर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)
10	मुख्य प्रशासन अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंधक (पो एण्ड आर्वाइ आर) प्रबंधक (कार्मिक) तारपुर परमाणु बिजली परियोजना 3 एवं 4 पोस्ट आफिस टी.ए.पी.पी जिला थाना, महाराष्ट्र	जिला थाना महाराष्ट्र में तारपुर परमाणु बिजली परियोजना यूनिट 3 एवं 4 में स्थूलतर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत अथवा उससे संबंधित परिसर (कार्यालय एवं आवासीय)

[संदर्भ सं. 6/1/(50)/88-पीपी 81]

मुनील पोरवल, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 18th February, 1991

S.O. 898.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy. S.O. No. 2365, dated the 14th August, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below being officers equivalent to the rank of gazetted officers of the government, to be Estate Officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

No.	Designation of the Officer	Categories of the Public Premises and in local limits of jurisdiction
1		2
1.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&R)/Manager (Personnel), Tarapur Atomic Station, P.O. Tarapur, Dist. Thane-401 504 (Maharashtra).	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Tarapur Atomic Power Station in Palghar & Dahanu Taluka, Dist. Thane. Maharashtra.
2.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&R)/Manager (Personnel), Madras Atomic Power Station, Kalpakkam-603102, Chengalpattu Dist. Tamil Nadu.	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Madras Atomic Power Station in Kalpakkam, Chengalpattu, Dist. Tamil Nadu.
3.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/Manager (Personnel), Rajasthan Atomic Power Station PO : Anushakti Via Kota, Rajasthan-323303.	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Rajasthan Atomic Power Station in Rawatbhatta Kherli (Anushakti) Vikram Nagar, Bhabha Nagar in Tehsil Begun, Dist. Chittorgarh, Rajasthan.
4.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/Manager (Personnel), Narora Atomic Power Project, PO Narora Via Debai, Bulandshar, Uttar Pradesh, Pin Code No. 202397	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Narora Atomic Power Project, PO Narora Via Debai, Bulandshar Dist. Uttar Pradesh.
5.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/Manager (Personnel), Kakrapar Atomic Power Project, Village Moticher, Mandvi Taluka, Dist. Surat, Gujarat.	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Kakrapar Atomic Power Project in village Moticher, Nanicher and Rajwad in the Mandvi Taluka and village Unchamala, Vyara Taluka, District Surat, Gujarat.
6.	Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/Manager (Personnel) Rajasthan Atomic Power Project 3 & 4 PO Anushakti, Via Kota, Rajasthan-323 303	Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Rajasthan Atomic Power Project 3 & 4 in Rawatbhatt, Kherli (Anushakti) Vikram Nagar, Bhabha Nagar in Tehsil Begun, Dist. Chittorgarh, Rajasthan.

1	2	3
7. Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/ Manager (Personnel) Kaiga Atomic Power Project, 977, Ram Krupa Ashram Road, Karwar, Uttar Kannada Dist. Karnataka-581 301.		Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Kaiga Atomic Power Project in village Mallapur, Kaiga, Karwar in Uttar Kannada District of Karnataka.
8. Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR), Manager (Personnel) Nuclear Power Corporation of India Limited, DAE Office complex, Vikram Sarabhai Bhavan, Anushakti Nagar, Bombay-400 094.		Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited, at its Headquarters office in Bombay, Liaison offices, Quality Surveillance offices, Registered office etc. located at various places in India.
9. Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR), Manager (Personnel) Rajasthan Atomic Power Project 5 to 8 PO : Anushakti Via Kota, Rajasthan 323 303.		Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Rajasthan Atomic Power Project 5 to 8 in Rawatbhata, Kherli (Anushakti), Vikram Nagar, Bhabha Nagar in Tehsil Begun, Dist. Chittorgarh, Rajasthan.
10. Chief Administrative Officer/Senior Manager (P&IR)/ Manager (Personnel), Tarapur Atomic Power Project- 3 & 4, PO TAPP, Thane District, Maharashtra.		Premises (Office & Residential) belonging to or under the management of the Nuclear Power Corporation of India Limited at Tarapur Atomic Power Project Unit 3 & 4 in Thane Dist. Maharashtra.

[Ref. No. 6/1(50)/89-PP81]

SUNIL PORWAL' Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1991

का. आ. 899—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस. 5 से जी. सी. एस. कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत् : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बसते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विभिन्न व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी. जी. एस. 5 से जी. सी. एस. कलोल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तहसील : कलोल

गांव	प्लॉक नं.	ह.	आर.	सेन्टीआर.
बोरीसाणा	911	0	36	00
	944	0	15	40
	943	0	06	60
	945	0	07	00
	946	0	15	00
	923	0	14	80
	968	0	00	80
	966	0	13	60
	965	0	08	10
	964	0	08	00
	958	0	12	00
काट्टेक		0	01	80
	309	0	04	10
	797	0	11	40
	798	0	30	00
	788	0	21	30
	789	0	02	60
	722	0	22	80
	790	0	06	00

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	कार्टट्रैक	0	02	40		235	0	04	90
	719	0	34	40		231	0	15	40
	689	0	26	10		233	0	10	00
	700	0	00	20		225	0	13	20
	690	0	17	20		कार्टट्रैक	0	01	00
	695	0	27	20	[सं. 0-11027/159/90-आ एन जी डी-II]				
	615	0	01	30					
	612	0	17	20	MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS				
	613	0	00	75					
	कार्टट्रैक	0	09	20	New Delhi, the 14th March, 1991				
	611	0	00	60					
	463	0	07	00	S.O. 899.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. V to GCS Kalol in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;				
	464	0	24	30					
	469	0	20	30	And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :				
	468	0	21	80					
	467	0	02	50	Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;				
	496	0	05	40					
	497	0	04	40	Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division Makarpura Road, Vadodara-390009.				
	393/2	0	20	30					
	393/1	0	07	70	And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.				
	कार्टट्रैक	0	05	20					
	393	0	09	40	SCHEDULE				
	392	0	00	15					
	346	0	07	20	PIPELINE FROM GGS-5 TO GCS KALOL				
	347	0	08	80					
	348	0	00	25	State : Gujarat District : Mhevana Taluka : Kalol				
	349	0	11	20					
	365	0	09	10	Village Block No. Hectare Acre Centiare				
	352	0	07	20					
	353	0	10	40	BORISANA	911	0	36	00
	354	0	09	20		944	0	15	40
	355	0	10	00		943	0	06	60
	356	0	10	60		945	0	07	00
	332	0	14	60		946	0	15	00
	327	0	01	60		923	0	14	80
	329	0	03	80		968	0	00	80
	328	0	12	20		966	0	13	60
	324	0	02	70		965	0	08	10
	कार्टट्रैक	0	01	40		964	0	08	00
	323	0	04	80		958	0	12	00
	कार्टट्रैक	0	01	10		Cart track	0	01	80
	243	0	09	80		809	0	04	10
	244	0	07	50		797	0	11	40
	245	0	05	00		798	0	30	00
						788	0	21	30
						789	0	02	60
						722	0	22	80
						790	0	06	00
						Cart track	0	02	40

1	2	3	4
719	0	34	40
689	0	26	10
700	0	60	20
690	0	17	20
625	0	27	20
615	0	01	30
612	0	17	20
613	0	00	75
Cart track	0	09	20
611	0	00	60
463	0	07	00
464	0	24	30
469	0	20	30
468	0	21	80
467	0	02	50
496	0	05	40
497	0	04	40
323/1	0	26	30
393/1	0	07	70
Cart track	0	05	20
323	0	09	40
392	0	00	15
346	0	07	20
347	0	08	80
348	0	10	25
349	0	11	20
365	0	09	10
352	0	07	20
353	0	10	40
354	0	09	20
35	0	10	00
356	0	10	60
332	0	14	60
327	0	01	60
329	0	03	60
328	0	12	20
324	0	02	70
Cart track	0	01	40
323	0	04	80
Cart track	0	01	10
243	0	09	80
244	0	07	50
245	0	05	00
235	0	04	90
234	0	15	40
233	0	10	00
225	0	13	20
Cart track	0	01	00

[No. O-11027/159/90—ONGD III]

का आ 900—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी.पी.एफ. गंधार से अपोलो टायर्स तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विस्थापित जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन का विस्थापन के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 30) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा

प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

प्रमाण कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन विधान के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी पी एफ गंधार से अपोलो टायर्स तक पाईपलाइन विस्थापन के लिए।

राज्य	गुजरात	जिला	भरुच,	तहसील	वांगरा
गांव	बलाकडन	हे	आर	से.	
साचण	60	0	00	30	
	59	0	08	85	
	299	0	12	64	
	58/ए	0	11	95	
	57	0	21	55	
	56/ए	0	37	70	
	56/सी	0	00	05	
	68	0	12	00	
	69	0	13	85	
	298	0	02	45	
	73	0	05	52	
	76	0	04	93	
	72	0	11	90	
	77/ए	0	15	85	
	118	0	13	05	
	119	0	24	63	
	145	0	67	82	
	152	0	06	30	
	153	0	09	95	
	154	0	09	83	
	155	0	12	55	
	158/ए	0	17	27	
	158/बी	0	05	03	
	158/सी	0	05	85	

[सं. ओ. 11027/160/90/आ. एन. बी. डी.-III]

S.O. 900.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CPF Gandhar to Apollo Tyres in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CPF GANDHAR TO APOLLO TYRES

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
Sachan	60	0	00	30
	59	0	08	85
	299	0	12	64
	58/A	0	11	95
	57	0	21	55
	56A	0	37	70
	56/C	0	00	05
	68	0	12	00
	69	0	13	85
	298	0	02	45
	73	0	05	52
	76	0	04	93
	72	0	11	90
	77/A	0	15	85
	118	0	13	00
	119	0	24	63
	145	0	67	82
	152	0	06	30
	153	0	09	95
	154	0	09	83
	155	0	12	55
	158/A	0	17	27
	157/B	0	05	03
	158/C	0	05	85

[No. O-11027/160/90-ONGD-III]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1991

का. प्रा. 901—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 2628, तारीख

6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार की पाईपलाइन को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

बी. एस. एच. बी से ब्लॉक जी. जी. एस. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला मेहसाना तालुका मेहसाना

गांव	सर्वे. नं.	हे.	आर.	से.
बलोल	875/2	0	14	76
	804	0	08	28
	874	0	05	16
	821	0	06	21
	820/4	0	03	24
	820/3	0	00	90
	827	0	12	24
	830	0	04	32

[सं. 0-11027/69/90-ओएनजीसी-III]

New Delhi, the 15th March, 1991

S.O. 901—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2628 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM BLHV TO BALOI GGS

State : Gujarat Distt. : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Baloi	875/2	0	14	67
	804	0	08	28
	874	0	05	16
	821	0	06	24
	820/4	0	03	12
	820/3	0	00	90
	827	0	12	24
	830	0	04	32

[No O-11027/69/90-ONGD-III]

का. आ. 902.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1952 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2606 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का गणना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचित में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय नेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई. पी. एम. में अक्लेश्वर सी. टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला मेहसाणा तालुका वागरा

गांव	ब्लॉक न.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
यहीवाल	कार्ट ट्रेक	0	06	80
	393	0	14	75
	394	0	26	25
	400	0	16	00
	395	0	16	75
	397	0	31	95
	361/ए/बी	0	37	15
	358	0	13	65
	357	0	15	60
	356	0	07	10
	355	0	09	50
	354/ए/बी	0	30	80

[सं. O-11027/113/90-ओ. एन. जी. डी-III]

S.O. 902.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2606 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM EPS TO ANKLESHWAR CTF

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Vahiyal	Cart track	0	06	80
	393	0	14	75
	394	0	26	25
	400	0	16	00
	395	0	16	75
	397	0	31	95
	361/A/B	0	37	15
	358	0	13	65
	357	0	15	60
	356	0	07	10
	355	0	09	50
	354/A/B	0	30	80

[No. O-11027/113/90-ONG D-III]

का. आ. 903.—यतः पेट्रोलियम और खनिज की पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3067 तारीख 17-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 717 GI/91—4

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकारी टी बिन्दु से जिप्को तक पार्श्व लाईन बिछाने के लिए (नया)

राज्य : गुजरात जिला : वडोदा तहसील : यादरा

गांव	प्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पावडा	कार्ट ट्रैक	0	01	80
	172	0	01	50
	165	0	02	50
	171	0	04	70
	170	0	04	40
	169	0	04	60
	168	0	05	00
	175	0	18	00
	149	0	31	40
	कार्ट ट्रैक	0	02	00
	148	0	17	00
	147	0	12	50
	कार्ट ट्रैक	0	01	00

[सं. O-11027/140/90-ओ. एम. जी. डी-III]

S.O. 903.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3067 dated 17-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CHOKARI T. POINT TO GIPCO

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Padra

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
Pavda	Cart track	0	01	80
	172	0	01	50
	165	0	02	50
	171	0	04	70
	170	0	04	40
	169	0	04	60
	168	0	05	00
	175	0	18	00
	149	0	31	40
	Cart track	0	02	00
	148	0	17	00
	147	0	12	50
	Cart track	0	01	00

[No. O-11027/140/90-ONG D-III]

का. आ. 904 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2610 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मन्त्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से सभी वाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पादरा ईपीएस से ए. के. सी. एल. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - वडोदरा तालुका - पादरा

गांव	ब्लॉक नं.	है	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
पादरा	961	0	07	50
	960	0	02	25
	962	0	03	50
	963	0	04	50
	964	0	02	40
	973	0	08	12
	974	0	03	58
	975	0	22	75
	1041/1/2	0	14	95
	1027/1/2	0	08	45
	1028	0	09	75
	1029	0	08	77
	1031	0	17	70
	1032/1	0	01	80
	1122	0	01	63
	1120	0	10	07
	1119	0	20	80
	1118	0	19	15
	1124/2	0	12	05
	1165	0	10	45
गाडावाट		0	01	95
	1260 1	0	29	90
	1254	0	00	30
	1259	0	11	25
	1257	0	03	25
	1257/2	0	10	40
	1257 1	0	12	15

[सं. O-11027/109/90-ओ. एन. जी डी-III]

S.O. 904.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2610 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM PADRA EPS TO AKCI

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Padara		
Village	Block No.	Hectare	Ac	Centiare
Padra	961	0	07	50
	960	0	02	25
	962	0	03	50
	963	0	04	50
	964	0	02	40
	973	0	08	12
	974	0	03	58
	975	0	22	75
	1041/1/2	0	14	95
	1027/1/2	0	08	45
	1028	0	09	75
	1029	0	08	77
	1031	0	17	70
	1032/1	0	01	80
	1122	0	01	63
	1120	0	10	07
	1119	0	20	80
	1118	0	19	15
	1124/2	0	12	05
	1165	0	10	45
	Cart track	0	01	95
	1260/1	0	29	90
	1254	0	00	30
	1259	0	11	25
	1257	0	03	25
	1257 2	0	10	40
	1257, 1	0	12	35

[No. O-11027/109/90-ONGD-III]

का.आ. 905.—यन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन सुविधा में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2618 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यन केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यन उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करना है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उम धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय नेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन ई पी से ई पी एम तक पाईप लाईन बिछाने के लिए
राज्य — गुजरात जिला — भरूच तालुका — वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	है.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
गंधार	322/ए/बी	3	71	02

[म. O-11027 108 90-ओ एन जी डी-III]

S.O. 905.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2618 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNEP to E.P.S.

State : Gujarat Distt . Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tare
Gandhar	322/A/B	3	71	02

[No. O-11/027/108/90-ONG D-III]

का.आ. 906.—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ० सं 2619 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत्. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन जी के में ई पी एस नेक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—वाग्र

गांव	ब्लॉक नं.	हे	आर	सन्टी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुसेर	74/ए	0	02	08
	73	0	06	76
	71	0	08	32
	72	0	08	32
	70	0	18	20
	69	0	06	24
	68	0	05	46
	63	2	06	18

[स O-11027/107/90 ओ एन जी डी-III]

S.O. 906.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2619 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGK to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tare
Muller	74/A	0	02	08
	73	0	06	76
	71	0	08	32
	72	0	08	32
	70	0	18	20
	69	0	06	24
	68	0	05	46
	63	2	06	18

[No. O-11027/107/90-ONG D-III]

का. आ. 907 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2622 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन० जी० के० से ई. पी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला—भरुच	तालुका—वाग्रा			
गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	सें.	
गंधार	322/ए/बी	1	09	56	

[सं. O-11027/105/90 ओ एन जी डी-III]

S.O. 907.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2622 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGK to L.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Arc 09	Centi- tiare
Gandhar	322/A/B	1	09	56

[No O-11027/105/90-ONG D-III]

का. आ. 908 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2651 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि

इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. डी. आई. (ii) से ई० पी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वाग्रा

गाव	ब्लॉक नं.	ह.	आर	में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुलेर	63	1	83	04

[सं. ओ-11027/100 90-ओ एन जी डी III]

S.O. 908.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2657 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNDI (11) to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Muller	63	1	83	04

[No. O-11027/100/90-ONGD-III]

का. आ. 909.—यतः : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 2615 तारीख 17-9-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कालोल जी.जी. एस. 1 में 11 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : गांधी नगर

गाव	ब्लॉक नं.	हैक्टर	आर	में
अडालज	576	0	15	80
	577	0	15	200
	578	0	14	8
	586	0	26	40
	587	0	30	00
	607	0	21	20
	608	0	22	40
	609	0	18	00
	610	0	13	80
	611	0	18	60
		0	01	00
तारापुर	134	0	21	00

[सं. O-11027/95/100-ओएन जी डी-III]

S.O. 909.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2615 dated 17-9-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kalol GGS I to XI

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Adalaj	576	0	15	80
	577	0	15	20
	578	0	14	80
	586	0	26	40
	587	0	30	00
	607	0	21	20
	608	0	22	40
	609	0	18	00
	610	0	13	80
	611	0	18	60
	Cart track	0	01	00
Tarapur	134	0	21	00

[No. O-11027/95/100-ONG D-III]

का आ. 910.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 2649 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, यत् उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन एफ सी (आई जी एन 21) से ई पी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए—

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : बागरा

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	एयर	सेन्टी.
(1)	(2)	(3)	(4)	
गंधार	7 322 ए. बी	1	89	93

[सं. O-11027/91/90-ओ एन जी डी-III].

S.O. 910.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2649 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNFC (IGN-21) to EPS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-tiare
Gandhar	322/A/B	1	89	93

[No. O-11027/91/90-ONG D-III]

का.आ. 911.—यतः पेट्रोलियम और खनिज की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2648 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियां में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए पद द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होते की वजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी जे ए के मे जी एन बी ग्राई हेडर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला—भरुच तालुका—वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कड़ोदरा	898	0	10	40
	897	0	14	56
	896	0	11	14
कार्टट्रैक		0	07	80
	862	0	03	90

[सं. O-11027/90-90—ओ एन जी डी-III]

S.O. 911.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2648 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from DJAK to GNBI Header

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-tiare
K. lodara	898	0	10	40
	897	0	14	56
	896	0	11	14
Cart track		0	07	80
	862	0	03	90

[No. C-11027/91/90-ONG D-III]

का. आ. 912 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 2640 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. डी. आई. (II) से ई. पी. एम. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ?

राज्य:—गुजरात जिला—भरूच तालुका—बागरा

गांव	ब्लॉक न.	हे.	आर.	सेन्टी.
चांचवेल	284	0	75	40

[स. O.-11027/86/90 ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 912.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2640 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

717 GI/91—5

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNDI (11) to FPS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagara

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Chanchwel	284	0	75	40

[No. O-11027/86/90/ONG D-III]

का. आ. 913 .—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 2638 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. जी. एन. से ई. पी. एस. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—भरूच	तालुका—बागरा		
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टीयर
चाम्बवेल	285	0	71	76

[स. O.-11027/78/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 913.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2638 dated 6-10-90 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGN to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Chanchwel	285	0	71	76

[No. O-11027/78/90-ONG D-III]

का. आ. 914.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2636 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कानावाडा-3 से कानावाडा-2 तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—खेडा	तालुका—खंभात		
गांव	स.नं.	हे.	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
कानावाडा	196	0	09	52
	187/2	0	04	62
	187/5	0	03	00
	187/1 + 3	0	00	21
	958	0	02	87
	186	0	05	39
	185	0	01	82
	12	0	01	33
	18/2	0	04	69
	19	0	02	52
	20	0	01	45
	22	0	03	22
	29	0	01	02
	28/2	0	00	63
	28/3	0	01	86
	48	0	01	68

1	2	3	4	5
	47	0	02	73
	53	0	05	95
	54	0	02	101
	61	0	02	10
	60	0	04	48
	59 1	0	02	38
	99	0	06	10

[सं. O.-11027/75'90 ओ.एन.जी.डी.0 III]

S.O. 914.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2636 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Kanawada-3 to Kanawada-2 (EPS)

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat

Village	Survey No.	Hec-tare	Arc	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kanawada	196	0	09	52
	187/2	0	04	62
	187/5	0	03	00
	187/1+3	0	00	21
	958	0	02	87
	186	0	05	39
	185	0	01	82
	12	0	01	33
	18/2	0	04	69
	19	0	02	52
	20	0	01	45
	22	0	03	22
	29	0	01	02
	28/2	0	00	63
	28/3	0	01	86
	48	0	01	68
	47	0	02	73
	53	0	05	95

1	2	3	4	5
	54	0	02	10
	61	0	02	10
	60	0	04	48
	59/1	0	02	38
	99	0	06	10

[No. O.-11027/75/90-ONG D-III]

का. आ. 915—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की (1) उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2644 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तैल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. जी. बाई से ई. पी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला: भरुच तालुका: वागरा
गांव ब्लोक न. हेक्टेयर आरे. सेन्टी
यर

1	2	3	4	5
मुलेर	63	1	30	00

[सं. O.-11027/71 90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 915.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2644 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGY to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Muller	63	1	30	00

[No. O-11027/71/90-ONGD-III]

का.आ. 916:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2621 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दी हैं।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. एच. डी. से ई. पी. एस. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: भरुच तालुका: वाग्रा

गांव	ब्लोक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
गन्धार	321	1	17	78
	322/ए/बी	0	88	88

[सं. O.-11027 104/90-ओएनजीडी-III]

S.O. 916.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2621 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNHD to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Gandhar	321	1	17	78
	322/A/B	0	87	88

[No. O-11027/104/90-ONGD. III]

का.आ. 917 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2625 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का आशय अपना घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. एन. जी. जे. मे. ई. पी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला: भरुच तालुका: वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टी-यर
गंधार	322 ए बी	1	64	06

[सं. ओ. 11027/101/90-ओ.एन.जी.डी.-III]

S.O. 917.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2625 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report of the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNGJ to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Cen- tare	Are 64	Cen- tiare
Gandhar	322/A/B	1	64	06

[No. O-11027/101/90-ONG D-III]

का.आ. 918 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2616 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों का उपयोग अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. ऐन. डी. आई. (11) से ई. पी. एस. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: भरुच तालुका: वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर आर.	सेन्टी-यर	
1	2	3	4	5
गंधार	322/ए/बी	3	82	24

[सं. ओ. 11027/94/90-ओ.एन.जी.डी.—III]

S.O. 918.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2616 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (50 of 1952), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report of the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GNDI (11) to E.P.S.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Gandhar	322/A/B	3	82	24

[No. O-11027/94/90/ONGD. III]

कां. आ. 919.—पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2617 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोग भूमियों का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी.एन. एफ. के. (आई.जी.एन. 29) से ई.पी.

एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: भरुच तालुका: वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
गंधार	321	1	29	08
	322/ए/बी	0	98	80

[सं.ओ. 11027/93/90-ओ.एन.जी.डी. III]

S.O. 919.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2617 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (50 of 1952), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report of the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication

of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from GNFK (IGN-29) to EPS

State	Gujarat	District	Bharuch	Taluka	Vagra
Village	Block No	Hec-tare	Are	Cen-tiare	
Gandhar	321	1	29	08	
	322/A/B	0	98	80	

[No O-11027/93/90-ONGD III]

का आ 920 —यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.म. 2650 तारीख 6-10-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी एन एफ. एम. (आई जी एन-43) से ई. पी. एम. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य	गुजरात	जिला	भरुच	तालुका	वाग्रा
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आरे	सेन्टी-यर	
	1	2	3	4	5
गंधार	321	1	76	80	
	322/ए/बी	1	12	45	

(स.ओ. 11027/92/90-ओ.एन.जी.डी.-III)
के. विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

SO 920—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2650 dated 6-10-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1952 (59 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report of the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from GNFS (IGN-43) to EPS

State	Gujarat	District	Bharuch	Taluka	Vagra
Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare	
Gandhar	321	1	76	80	
	322/A/B	1	12	45	

[No 11027/92/90-ONGD, III]
K. VIVEKANAND, Desk Officer

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1991

का.आ. 921—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगड में मौजे बोरीस, तहसील अलिबाग में मौजे मालात्र तहसिल मुण्ड अजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन मैसर्स ग्रामीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 91 साखर भवन, नरिमन पार्क, मुंबई 400 021 बम्बई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रभू बिल्डिंग, तहसील अलीबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः वह भी कथन करेगा कि यह चाहता है कि मुनवाई व्यक्तिगत स्वरूप से हो या किसी विधायी व्यवहारी के मार्फत।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		जिला रायगढ़		तहसील : अलीबाग		
गांव	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर	सेआर
वायशेत	11	2 भाग	—	0	35	59

सं. 14016/45/85-जी.पी.

(Department of Petroleum and Natural Gas)

New Delhi, the 14th March, 1991

S.O. 921.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Boris, Tahsil Alibag, District Raigad to village Salav, Tahsil Murud (Janjira), Distt. Raigad in the State of Maharashtra, Pipeline should be laid through the Agency of Grasim Industries Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such Pipe Lines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the lands referred in the schedule.

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the Pipe Lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of the Notification, to the Competent Authority, Grasim Industries Ltd., Prabhu Building, Alibag, Distt. Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra		District : Raigad		Tahasil : Alibag		
Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area		
				Hector	Acre	Centiare
Vaishet	11	2 Part	—	0	35	59

[No. 14016/45/85 GP]

का.आ. 922.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलीबाग से मौजे सालाव, तहसील मुरुड जंजिरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन मैसर्स ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 91 साखर भवन, नरिमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 बम्बई द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रभू बिल्डिंग, तहसील अलीबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह कथन करेगा कि यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

परिशिष्ट

राज्य : महाराष्ट्र		जिला : रायगढ़		तहसील : अलीबाग		
गांव	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र		
				हेक्टर	आर	सेंटीआर
तुडाल	1	1-बी भाग	—	0	08	70

[सं. 14016/45/85-जी.पी.]

S.O. 922.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Boris, Tahsil Alibag District Raigad to Village Salav, Tahsil Murud (Jangira), Distt. Raigad in the State of Maharashtra, Pipe Line should be laid through the Agency of Grasim Industries Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Nariman Point, Bombay-400021.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such Pipe Lines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the lands referred in the Schedule :

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the Pipe Lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of the Notification, to the Competent Authority, Grasim Industries Ltd., Prabhu Building, Alibag, Distt. Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE						
State : Maharashtra		District : Raigad		Tahasil : Alibag		
Village	Survey No.	Hissa No.	Gat No.	Area Hectrr	Are	Contiare
Tudal	1	1-B Part	—	0	08	70

[No. 14016/45/85-GP]

का.आ. 923.—यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य, जिला रायगढ़ में मौजे बोरीस, तहसील अलीबाग से मौजे सालाव, तहसील मुरुड जंजीरा तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिए पाईप लाईन सैसस ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 91 साखर भवन, नरिमान पॉइंट, मुंबई 400 021 बम्बई द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रयोजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रभू बिन्डिंग, तहसील अलीबाग को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

राज्य महाराष्ट्र	परिशिष्ट		तहसील	अलीबाग
	जिला	रायगड		
गांव	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	गट नंबर	क्षेत्र
				हेक्टर आर सेटीआर
गुंजीस	33	1 पार्ट	—	0 02 96
	45	4-ए पार्ट	—	0 02 85

[म. 14016/45/85-जी. पी.]

S.O. 923.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas, from Boris, Tahsil Alibag District Raigad to Village Salav, Tahsil Murud (Janjira), Distt. Raigad in the State of Maharashtra, Pipe Line should be laid through the Agency of Grasim Industries Ltd., 91, Sakhar Bhavan, Naiman Point, Bombay-400021.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such Pipe Lines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals

Pipe Lines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user in the lands referred in the Schedule

Provided that any person interested in the said lands having any objection for laying the Pipe Lines through the said lands may prefer any objection within 21 days from the date of the Notification, to the Competent Authority, Grasim Industries Ltd., Prabhu Building, Alibag, Distt. Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

State : Maharashtra		District : Raigad		Tahasil : Alibag		
Village	Survey No	Hissa No.	Gat No.	Area		
				Hector	Arc	Centiare
Gunjis	33	1 Part	—	0	02	96
	45	4-A Part	—	0	02	85

[No. 14016/45/85-GP]

का आ 924—भारत के राजपत्र ता 1-12-90 में प्रकाशित अधिसूचना (पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय) ता 1 नवम्बर 90 में निचेलिखे हुए स्थान

अ. क्र.	ग्राम	अधिसूचना नं.	प्लॉट नं.	मंजूरिया नं.	पड़िये	के स्थान पर
					हे आ	से आ हे आ से आ
1.	गुंजीस	3225	5140	1	0-10-95	0-01-95
2.	साव	3222	5135/36	3	0-19-63	0-09-63
				15	0-10-66	0-01-66
3.	दरसोली	3217	5129	15	0-10-20	0-01-20
4.	उधेशी	3215	5125/26	1	0-10-98	0-01-98
5.	कुसुद	3214	5122/23	27	0-20-24	0-02-24
				29	0-10-40	0-01-40
6.	बैलकटे	3212	5118	27	0-10-84	0-01-84
			5119			
7.	कुवर	3213	5120	8	0-20-79	0-02-19
			5121	20	0-10-08	0-01-08

1	2	3	4	5	6	7
8	महाण गांव	3211	5116/17	32	0-20-49	0-02-49
9	कावीर	3210	5114/15	16	0-10-44	0-01-44
10	वेल्लवला	3207	5110	5	0-10-14	0-01-14
				12	0-20-64	0-02-64
11	खानाव	3206	5107/8	14	0-10-70	0-01-70
					0-10-35	0-01-35
12	चौल	3203	5100/1	10	0-10-48	0-01-48

पृष्ठ नंबर 5130 पर लोशरे नाम के स्थान पर लाणरे पढ़िये।

पृष्ठ नंबर 5126 पर वेशनी नाम के स्थान पर वेश्वी पढ़िये।

[No. 14016, 45/85 GPJRT]

गजिव महर्षि, उप मंत्री

S.O. 924 . - In the Notification dated 9-11-90 published in Bharat Gazette dated 1-12-90, Part II, Khand 3(ii) by the Petroleum & Rasayan Mantrayala, substitute the figures as below:

S. No	Village	S. No. of Notification	Page No	Line No	Read			in place of		
					H.	Are	Care	H.	Are.	Care
1.	Gunjis	3225	5140	1	0-10-95			0-01-95		
2.	Bhal	3222	3115/36	3	0-19-63			0-09-63		
				15	0-10-66			0-01-66		
3.	Varsoli	3217	5129	15	0-10-20			0-01-20		
4.	Veshvi	3215	5125/26	1	0-10-98			0-01-98		
5.	Kurul	3214	5122/23	22	0-20-24			0-02-24		
				29	0-10-40			0-01-40		
6.	Belkade	3212	5118, 5119	27	0-10-84			0-01-84		
7.	Dhavar	3213	5120	8	0-20-79			0-02-79		
			5121	20	0-10-08			0-01-08		
8.	Sahan	3211	5116/17	32	0-20-49			0-02-49		
9.	Kavir	3210	5114/15	16	0-10-44			0-01-44		
10.	Velhavli	3207	5110	5	0-10-14			0-01-14		
				12	0-20-64			0-02-64		
11	Khanav	3206	5107/8	14	0-10-70			0-01-70		
					0-10-35			0-01-35		
12.	Choul	3203	5100/1	10	0-10-48			0-01-48		
					0-10-73			0-01-73		

At Page No. 5130 Read Lonare instead of Loshare

At Page No. 5126 Read Veshvi instead of Veshni

[No 14016/45/85. GPJRAJIV MEHRSHI, Dy Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1991

का.आ 925 --चलचित्र अधिनियम 1952(1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 7 और 8 तथा उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय की दिनांक 6-11-90 की समसंख्यक अधिसूचना के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वगलौर सलाहकार पैनल में निम्नलिखित व्यक्तियों को अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव में नियुक्त करती है --

1. श्रीमती शुभा
2. श्रीमती सुनन्दा पी जाधव
3. श्रीमती पी.वी. गीता
4. श्रीमती एम. चित्रलेखा
5. डा. रमाकांत बेनसन
6. श्रीमती एस. एस. श्रीमती
7. श्रीमती मध्या नानजुडिहा

8. सुश्री अंदानूर शोभा
9. डा. एस.एडविन रत्नाशीला
10. डा. (श्रीमती) नानजू वारकेय
11. श्री एम. के. राव
12. श्रीमती लक्ष्मी निजामुद्दीन
13. श्री एस. डी. मैथूरमठ
14. सुश्री अश्विनी नाचप्पा
15. श्री बी हरीशचन्द्र भट्ट
16. श्री वाई. एस. बी. दत्ता
17. श्री मोहन कोडाजी
18. श्री एस. कृष्णा शेटी
19. श्रीमती स्वर्ण प्रभाकर
20. श्री कोटीगनाहल्ली रमैय्या
21. श्रीमती एस. जी. त्रिग्रेनका
22. श्री यू. भूपति
23. सुश्री सुधा शंकर
24. सुश्री पार्वती नानजप्पा
25. वृ. हेमा चौधरी।

[का.स 314/8/90-एफ(सी)]

टी. ए. आर. प्रमुख, टेक अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th February, 1991

S.O. 925.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) and rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated 6-11-90 on the subject, the Central Government is pleased to appoint the following persons in the Bangalore Advisory Panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect and until further orders :—

1. Smt. Shubha
2. Smt. Sananda P. Jadhav
3. Smt. P. V. Geetha
4. Smt. S. Chitulekha
5. Dr. Ramakanth Venson
6. Smt. H. S. Sreemathi
7. Smt. Sandhya Nanjundiah
8. Ms. Andanur Shoba
9. Dr. S. Edwin Rathna Sheela
10. Dr. (Smt.) Nanjoo Varkey
11. Shri M. K. Rao
12. Smt. Lakshmi Nizamuddin
13. Shri S. G. Mysoremath
14. Ms. Aswini Nachappa
15. Shri B. Harishchandra Bhat
16. Shri Y. S. V. Datta
17. Shri Mohan Kondajji
18. Shri C. S. Krishna Shetty
19. Smt. Swarna Prabhakar
20. Shri Kotiganahalli Ramaiah
21. Smt. S. G. Tungarenuka
22. Shri U. Bhoopathi
23. Ms. Sudha Shankar
24. Ms. Parvathi Nanjappa
25. Kum. Hema Choudari.

[File No. 814/8/90-F(C)]
T. S. ARASU, Desk Officer

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1991

का. मा. 926.—राष्ट्रपति, पवनहंस लिमिटेड के शापन एवं संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद 38(क) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. एम. भारद्वाज, सयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को, श्री पी. के. बैनर्जी, सयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर, जिनकी नियुक्ति इस मंत्रालय की दिनांक 17-1-91 की अधिसूचना संख्या ए बी-13015/81/88-ए. सी. (बी. एल.) के द्वारा अधिसूचित की गई थी, तत्काल से और 16 जनवरी, 1994 तक, पवनहंस लिमिटेड के बोर्ड में पदेन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

[संख्या एबी-13015/81/88-ए.सी.वा.एल.]

नसीब सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th March, 1991

S.O. 926.—In exercise of the powers conferred by Article 38(a) of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Limited, the President is pleased to appoint Shri A. M. Bhardwai, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation as Ex-Officio Director on the Board of Pawan Hans Limited with immediate effect and until 16th January, 1994 vice Shri P. K. Banerji, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, whose appointment was earlier notified vide this Ministry's notification No. Av 13015/81/88-ACVI, dated 17-1-1991.

[No. Av. 13015/81/88-ACVI]
NASIB SINGH, Under Secy

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1991

का. मा. 927.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, लखनऊ के प्रबन्धतंत्र के संबंध में नियोजका और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 4-3-91 का प्रारण हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 4th March, 1991

S.O. 927.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on 4-3-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

PRESENT:

Shri Arjan Dev, Presiding Officer,
Industrial Dispute No. 248 of 1989

In the matter of dispute between:

The Divisional Secretary,
Uttar Railway Karamchhari Union,
39-II-J, Multistoreyed Building,
Rly. Colony Charbagh, Lucknow.

AND

The Divisional Rly. Manager,
Northern Railway,
Hazaratganj, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41012/45/88-D-2(B), dated 5-10-89, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the Divisional Rly. Manager, N. Rly., Lucknow was justified in suspending Shri Ram Swarup S/o Shri. Dwarka Prasad Porter w.e.f. 22-5-87 without any notice? If not, to what relief the workman was entitled to?

2. On 13-2-91, Shri B. D. Tiwari, who represents the Union submitted that the workman is not now under suspension, he is working. Therefore, the reference has become infructuous.

3. I may state here that even in the written statement it has been pleaded by the management that railway administration also revoke the order of suspension on 15-7-87, and according to the management the workman has not thereafter reported for duty. Shri Ravi Jauhari, who represented the management also submitted that presently the workman is working.

4. In view of the above facts it was rightly submitted by Shri Tiwari that the reference has become infructuous. Accordingly it is held that the reference has become infructuous. But it will not effect the right of the workman to claim any relief on the basis of his suspension in future.

5. Reference is answered accordingly

ARIAN DEV, Presiding Officer
[No. L-41012/45/88-D II(B)(Pt.)]

का. आ. 928.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पचपद का प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार का 4-3-91 का प्राप्त हुआ था।

S.O. 928.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of DRM, Northern Railway, Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on 4-3-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DEOKI PLACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 70 of 1988

In the matter of dispute between :

Shri G. S. Trivedi,
President, Uttar Railway Karamchari Union
130/90/26(L-1), Bagahi Transport Nagar,
Kanpur.

AND

The General Manager,
Northern Railway Baroda House
New Delhi.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-41012/59/87-D.II(B) dated 30-5-88 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

Whether the action of the management of DRM, Northern Railway, Allahabad in terminating Shri Ram Lal from service with effect from 18-1-83 is legal and justified? If not, to what relief and from what, he is entitled to?

2. The Industrial Dispute on behalf of the workman Shri Ram Lal has been raised by Uttar Railway Karamchari Union (hereinafter referred to as Union for brevity).

3. The admitted facts are that the workman who was posted as Safaiwala at Samho Railway Station, was served with a major penalty chargesheet dated 24-8-82. He stood charged on the following two grounds—

Article No. 1 :—Shri Ram Lal while functioning as A Safaiwala failed to maintain absolute integrity and devotion to duty and he remained on unauthorized absence from duty for the period from 27-6-82 to 6-8-82.

Article No. 2 :—For leaving station without permission for CNB. Shri R. S. Sing Chauhan T.I. was appointed Enquiry Officer. The enquiry proceeded ex parte against the workman and ex parte inquiry report was given by the E.O. holding the charges as proved on 8-1-83. The DTS Tundla, who was the Disciplinary Authority accepted his findings and awarded the punishment of removal from service to the workman. The workman filed an appeal also filed an application for review of the order of punishment but without any success.

4. The Union's case in short is that the workman joined the services of the railway on 28-11-58. In March 1982 he was posted as Safaiwala at Samho Rly. Station. The Union has challenged the order of punishment on a number of grounds. According to the Union, the chargesheet was ambiguous and vague, it did not disclose the name of the station nor copies of documents to be relied upon in support of the charges were given to the workman. Copy of findings given by the E.O. were also not given to the workman, the Appellate Authority did not give him any personal hearing. The Additional D.R.M. who heard his review petition was not the competent authority to decide his review petition. The order of removal from service amounted to retrenchment but while ordering his retrenchment no compliance was made of the provisions of section 25F I. D. Act. The punishment awarded was highly disproportionate. The workman had submitted a valid certificate regarding the illness of his wife and during his 25 years long service he had never been awarded any punishment. The Union, has, therefore, prayed that after setting aside the order of punishment, the workman be reinstated in service with full back wages and all consequential benefits.

5. In defence, the management plead that the inquiry proceedings were legal and were completed after observing all formalities. The workman was allowed full opportunity to defend himself before the disciplinary authority. The management deny that the services of the workman was illegally terminated by the disciplinary authority. The fact of the case did not attract the provisions of sec. 25F I.D. Act. The chargesheet was not vague. Even the other grounds on which the order of punishment has been challenged by the Union have no force. Lastly, it is pleaded by the management that the Tribunal has no jurisdiction to sit in revision or appeal over the final orders passed by the Disciplinary Authority.

6. In support of its case, the Union has examined the workman and as relied upon documents filed by the workman with his affidavit. On the other hand, the management have examined Shri Anand Kumar Head Clerk D.R.M. Office, Allahabad.

7. During the course of his submission, it has been urged by Shri Bhupendra Singh, the auth. representative for the workman that although from the evidence on record it is amply proved that the departmental proceedings were not concluded fairly and properly and that the ex parte report given by the E.O. and accepted by the disciplinary authority and appellate authority and even by the reviewing authority, is not based on evidence, he will argue the case only on the quantum of sentence in order to save the time of the Tribunal as in the event of the tribunal holding that the inquiry was not conducted fairly and properly

and that the *ex parte* finding is not based on evidence, the tribunal may permit the management to lead evidence to prove the charges which may take another 2-3 years time. If it is so done, the workman who is already out of service for the past 7-8 years might be completely ruined. His past record of service is good. he was never awarded any punishment prior to it. He left the station of his posting with the prior permission of the Station Master Samho on hearing the illness of his wife. This will stand proved from annexure 'g' to workman's affidavit which is the copy of the application dt. 26-6-82 given by the workman bearing the order of the Station Master Samho. In his said application he has written that since the condition of his wife is very bad, he should be permitted to go to Kanpur so that he could look after her properly. The order that was passed by Station Master was —

AAGYA DJ JATI HAI

There is no evidence in rebuttal from the side of the management. In the background of these circumstances, the Tribunal should interfere with the order of punishment passed by the Disciplinary Authority in exercise of its powers under sec. 11-A I.D. Act. The Tribunal should held the punishment as highly disproportionate of the charges framed against the workman and order his reinstatement and award him such punishment as it deems just in the circumstances of the case.

8. From the other side Shri S.C. Dubey, auth. representative for the management has argued that there is no force in any of the points raised by Shri Bhupender Singh. The inquiry was conducted by the E.O. fairly and properly in accordance with the principles of natural justice. The findings given by the E.O. and accepted by the Disciplinary Authority and also by the Appellate Authority etc. cannot be said as based on no evidence. It is wrong to suggest that the past record of service of the workman is good. He did leave the station for Kanpur without permission. The punishment awarded is quite just and proper and it does not call for any interference at the hands of the Tribunal in exercise of its power u/s 11-A of the Act.

9. After hearing the two sides I find a good deal of force in the submissions made by Shri Bhupendra Singh. With his affidavit the workman has filed the copy of Major Penalty Chargesheet dt. 24-8-82 served on him. Annexure 3 to the chargesheet refers to the evidence which would be relied upon by the management in support of the two charges. In support of charge No. 1 it is stated that the management would rely on the letter no. nil dt. 6-8-83 of the Station Master Samho and on charge no. 2, the management would rely upon letter no. 3/Transfer/82 dt. 14-8-82 of the Station Master Samho. It further appears from annexure 3 that on charge no. 1 the management was also relying on the statement of Station Master Samho. There is nothing to show that the copies of the above mentioned two letters wherever supplied by the disciplinary authority to the workman with the chargesheet. There is also no evidence from the side of the management to show that these copies were furnished by the E.O. to the workman during the inquiry proceedings. Thus it stands proved that the copies of the documents to be relied upon by

the management in support of the two charges were not furnished to the workman.

10. Next I come to the inquiry report. The copy of inquiry report dt. 8-1-83 was also filed by the management on the date of argument. It shows that the charges were taken as proved against the workman and that the workman was called upon to disprove the charges. There is nothing to show that the Station Master was examined in support of the charges. Even there is no reference of the two letters of the Station Master Samho referred to Annexure 3 to the chargesheet. From Annexure 2 to the chargesheet it appears that after leaving station without permission for Kanpur the workman submitted an irregular PMC in support of sickness of his wife from a private doctor on 3-8-82. We have seen above that from annexure 'g' to the affidavit of the workman it is found that the workman left station of his posting on hearing about the illness of his wife with the prior permission of the Station Master Samho and that there is no evidence in rebuttal from the side of the management. There is no discussion in the inquiry report as to how and under what rule of Railway, the medical certificate furnished by the workman was irregular or why the medical certificate so furnished by the workman deserved to be discarded. Thus the finding given by the E.O. and accepted by the disciplinary authority and other higher authorities cannot be said as based on any evidence worth consideration. It appears that neither the E.O. nor the disciplinary authority nor even appellate authority care to read the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules 1968. In this connection it would be sufficient if reference is made to Rule 10(I) and (II) of the said Rules. Rule 10(I) lays down that if the disciplinary authority is of the opinion that for examination of any of the witness is necessary in the interest of justice it may recall the witness and may impose on the railway servant such penalty as is within its competence in accordance with the rule. Rule 10(II) lays down that the disciplinary authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remand the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold further inquiry according to Rule 9. Thus in the present case on finding that while giving *ex parte* findings, the E.O. had not taken into consideration any evidence in support of the charges, the disciplinary authority could have referred the matter to the inquiry officer over again for taking down evidence of the witness and considering other material documentary evidence.

11. Annexure E to the affidavit of the workman is the copy of order of punishment dt. 10-1-1983. passed by DTS Tundla. He did not care to touch the evidence. He simply relied upon the inquiry report given by the E.O. with his eyes shut. I may state here that the copies of order of the appellate authority and reviewing authority have not been filed by either side.

12. In the present case, the copy of inquiry report has been filed to show that the workman deliberately avoided to participate in the inquiry. The same thing has been attempted to be shown from the affidavit of the management witness and with his affidavit has filed some documents which are copies of letters and

telegram to show that attempts were made to give information of the dates fixed in the inquiry to the workman. May it be so, but as has been found by me above it cannot be held that the inquiry was conducted fairly and properly in accordance with the principles of natural justice and that the exparte report given by the E.O. and accepted by the disciplinary authority and other higher authorities is perverse being not based on evidence. The result therefore would have been of setting aside the order of punishment and giving an opportunity to the management to lead evidence to prove charges.

13. We have seen above that the workman left Railway Station Samho on hearing the illness of his wife with the permission of the Station Master Samho. There is no evidence from the side of the management to prove that the past record of the workman is bad. In annexure 2 to the chargesheet it was stated by the disciplinary authority that the past record of the workman showed that he was habitual offender of absence from duty. No such record has been produced by the management before the Tribunal. Therefore, the only two things remains against the workman—

One is that he was on unauthorised absence from 27-6-82 to 3-8-82 and the second is that the medical certificate of the sickness of his wife produced by the workman of a private doctor was irregular.

Firstly it will not be just and proper to reorder inquiry after 7 or 8 years and secondly even if these two charges are ultimately held as proved they are not sufficient to warrant the punishment of removal from service. I must say that Sh. Bhupender Singh, the authorised representative for the workman has shown, while arguing this case, a lot of maturity and wisdom on his part and has rightly submitted that the punishment awarded by the management should be substituted by such punishment as may be deemed just and proper by the Tribunal in the circumstances of the case.

14. At the very outset I may state here that the workman has already under gone a lot of suffering and mental torture out of service for such a considerable time of 7 or 8 years during these hard days and to my mind at the most the punishment of stoppage of one annual graded increment with cumulative effect will meet the ends of justice.

15. Hence, it is held that the action of the management in awarding the punishment of removal from service to the concerned workman Shri Ram Lal w.e.f. 18-1-1983 is totally unjustified. In exercise of the powers under sec. 11 A of the Act, looking to the above facts and circumstances, the punishment of removal is substituted by stoppage of one annual graded increment with cumulative effect, (the annual increment which would have fallen due in 1983). The workman will be reinstated in service with full back wages and all consequential benefits.

16 Reference is answered accordingly.

[No. L-41012/59/87-D.II(B)(Pt.)]
ARJAN DEV, Presiding Officer

का आ. 929 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे लखनऊ के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पक्षपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 929.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on 4-3-91.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL DEOKI PALACE ROAD
PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 168 OF 1989

In the matter of dispute between :

The Divisional Secretary Uttar Railway Karamchari Union, 39-II-J Multistoreyed Railway Colony, Charbagh Lucknow.

And

Senior D.D.O. Northern Rly. Hazrat Ganj, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-41012/31/88D-2(B) dated 19-7-89, has referred the following dispute for adjudication this Tribunal :

Whether the Sr. D.P.O. and Sr. DSTE Northern Rly. Lucknow were justified in not extending the up-gradation benefit to Shri Jagdish Prasad Tiwari w.e.f. 1-6-78 ? If not, what relief the workmen was entitled?

2. On 13-2-91, Shri B. D. Tiwari, in this capacity as President, Uttar Railway Karamchari Union, submitted that since the workman has filed a petition before the Central Administrative Tribunal, Allahabad, the Union does not press the dispute referred to by the Ministry of Labour to this Tribunal.

3. In view of the above statement of Sh. Tiwari, the dispute raised by the Union on behalf of the workman is treated as not pressed.

4. It is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer
[No. L-41012/31/88-D-II(B)(Pt.)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1991

का आ. 930 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नावा काजोरा कार्यालयी आफ मैसर्स ई. सी. लि० के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के

बीच, अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसानसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th March, 1991

S.O. 930.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol, as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Naba Kajora Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-3-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL REFERENCE NO. 37/89

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Naba Kajora Colliery of M/s Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P.K. Das, Advocate.
For the Workman—Sri C D. Dwevedi, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.
Dated the 13th February, 1991

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. I-22012(14)/89-IR(C-II) dated the 21st July, 1989.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Naba Kajora Colliery (No. 7 Pit) of Eastern Coalfields Ltd., in refusing to allow Sri Moti Mia On setter to resume his duties is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled."

2. The case is taken up for hearing today (13-2-91). At this stage Sri D. C. Dwevedi the learned Advocate for the union submits that he has no instruction to proceed with the case and makes endorsement to that effect. In such circumstances it appears to me that no dispute exists between the parties and as such a no-dispute award is passed.

N. K. SAHA, Presiding Officer
[No. I-22012(14)/89-IR(C-II)]

का.ग्रा. 931.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नचा कालियरी अधीन मतग्राम एरिया आफ सैमर्ज ई. सी. लि., डा. जयकया नगर, जि. बर्दवान के प्रबन्धसल के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसानसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 931.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery under Satgram Area of M/s. E.C. Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-3-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL REFERENCE NO. 42/89

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P.K. Das, Advocate.
For the Workman—Sri Bijoy Kumar, Joint Secretary of the union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal
Dated, the 8th February, 1991

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(49)/89-IR(C.II) dated 27-9-1989.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Nimcha Colliery under Satgram Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan in not regularising the services of Sri Swapan Mukherjee as Lamps Issue Clerk in Clerical Grade II w.e.f. May, 1980 was justified ? If not to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case was taken up for hearing to-day (8-2-91). Sri Bijoy Kumar, Joint Secretary of the

concerned union again prays for time on the ground that he did not receive any information. On the last occasion time was allowed as last chance on the prayer of the union. So it appears to me that the union is not very keen for the disposal of the case. In such circumstances, I find no other alternative but pass a no-dispute award. Accordingly a no-dispute award is passed.

N. K. SAHA, Presiding Officer
[No. L-22012(49)/89-IR(C.II)]

का.घा. 932.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चिनाकुरी 3 पिट्स कोलियरी आफ मैसर्स ई. सी. लि. के प्रबन्धन से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 932.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Chinakuri 3 pits Colliery of M/s. E.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on the 4-3-1991.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL

Reference No. 14/88

PARTIES :

Employers in relation to the management of Chinakuri 3 Pits Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. N. Lala, Advocate.
For the Workman—Shri C. D. Dwevedi, Advocate.

INDUSTRY:—Coal. STATE:—West Bengal.
Dated, the 14th February, 1991.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L 24012(122)/87-D.IV(B) dated the 26th February, 1988.

717 GI/91—7

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Chinakuri 3 pits colliery in not recording the year of birth of Smt. Sadari Mejhian, W. L. Kamin as per identity card issued by the Management in the newly prepared Form B Register, is justified? If not, to what relief the workman is entitled.

2. The case was taken up for hearing to-day (14-2-91). Sri C. D. Dwevedi, the learned Advocate for the union again prays for time for settlement. I find from the record that this is a case of 1988 and the case has been pending since 11-1-90 for settlement. It appear to me that the parties are not very keen to get the matter settled. I further find that no dispute exists between the parties. As such they are not taking proper steps for disposal of the case.

3. In such circumstances I find no other alternative but to pass a no-dispute award and accordingly a no-dispute award is passed.

N. K. SAHA, Presiding Officer
[No. I-24012(122)/87-D.IV)]
RAJA LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1991

का.घा. 933.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धन से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th March, 1991

S.O. 933.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI R.C. BHATT, CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Ref. (I.T.C.) No. 8/89

State Bank of India,
Vadodara.

.... 1st party

Vs.

Employees working in it

.... 2nd party

The management of the State Bank of India, Vadod Branch, has terminated its ex-Cashier, Shri P. N. Champaneria, from 14-5-83. Whether this action is just and proper? If not, to what relief is the employee entitled?

AWARD

1. As stated in the index to the order No. L-12012/254/88-D-3/A, dated 18-1-89, of the Desk officer, Labour Ministry, Government of India, New Delhi, the management of the Valsad Branch of the State Bank of India, Vadodara, in the matter between the Bank and its employees, has terminated the service of its ex-cashier, Shri U. N. Champaneria, from 14-5-83. Whether the said action is just and proper? And to what relief is the employee entitled? The industrial dispute to this effect has been made and passed on for adjudication under Section 10 of the Industrial Disputes Act, vide reference.

2. During the hearing of this reference, the parties have submitted the pursis of the compromise vide Exh. 12. On a perusal of the conditions of the compromise, they seem to be proper and legal. And it seems that industrial peace will be maintained by passing the order accordingly. I, therefore, pass the order as under :

ORDER

3. [The parties to act as per the conditions of compromise as per pursis at Exh. 12. A copy of the pursis of compromise at Exh. 12 to be kept with this judgement. The pursis of compromise at Exh. 12 to be reckoned as a part of this Award. In view of the circumstances, no order as to costs is passed.]

R. C. BHATT, Central Industrial Tribunal
[No. L-12012/254/88-II(A)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

**BEFORE THE HON. INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT AHMEDABAD**

Reference 1. T. C. No. 8 of 1989

BETWEEN:

State Bank of India,
Baroda. ...

V/S.

Shri P. N. Champaneria.

CONSENT TERM

1. parties in the aforesaid reference have arrived at the Settlement and it is prayed that this Hon. Tribunal be pleased to pass the Award in terms of the Settlement appended below :—

TERMS OF THE SETTLEMENT

- (i) That the Bank shall reinstate the workman Shri P. N. Champaneria on his original post and place within 15 days from to-day.
- (ii) That the Bank shall count the period of service from 14-8-1982 till he is actually reinstated as continuous service. The said period will not be taken into consideration for grant of pension, seniority and increment.

(iii) That his basic salary on reinstatement will be the amount which he was drawing as basic wages as on 14-6-1982 and will be entitled to his next increment as usual.

(iv) It is clearly understood between the parties that the workman has foregone the claim of back wages for the period from 14-8-1982 till he is actually reinstated by the Bank.

(v) That this settlement is full and final settlement of all the claims raised in the present reference and that the workman agrees not to raise any further dispute with regard to the subject matter of the present reference.

2. That the parties pray that this Hon. Tribunal to record the present Consent Term and pass the Award in the aforesaid Reference.

1. Representing State Bank of India.
2. Shri P. N. Champaneria
3. Advocate for the First Party Bank.
4. Advocate for the second party workman

AHMEDABAD.

DATED : 5/11/1990

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1991

का. आ. 934.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) में उपखंड (V) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2676 दिनांक 20 सितम्बर, 1990 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 सितम्बर, 1990 से छः मास की कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोग के लिए 20 मार्च, 1991 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/14/85-डी-1(ए)]

New Delhi, the 18th March, 1991

S.O 934.—Whereas the Central Government having been satisfied that the 'Public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2676 dated 20th September, 1990 the Bank Note Press, Dewas (MP) to be a public utility service for the period of six months, from the 20th September, 1990;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 20th March, 1991.

[No. S-11017/14'85-D.I(A)]

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1991

का. आ 935 —केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2820 दिनांक 15 अक्टूबर, 1990 द्वारा पाइराइट्स खनन उद्योग की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 अक्टूबर, 1990 में छ मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 अप्रैल, 1991 से छ मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/1/80-आई आर. (नीति)]

बी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th March, 1991

S.O. 935.—Whereas the Central Government having been satisfied that the Public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 2820 dated the 15th October, 1990 the Pyrites Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 15th October, 1990;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service

for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 15th April, 1991.

[No. S-11017/14'85-D.I(A)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 18-3-1991

का. आ 936 —कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ-27 के उप पैराग्राफ (2) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, पूर्वनाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के का.आ संख्या 3255, दिनांक 12 नवंबर, 1963 की अधिसूचना का अतिश्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उन स्थापनाओं के नियोजता जिनके कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैराग्राफ 27 के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जिस माह की रिपोर्ट हो इसके आगे आने वाले माह की 25 तारीख तक सलग्न अनुसूची में दिये गये प्रोफार्मा में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अनुसूची

जिन स्थापनाओं के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैराग्राफ-27 के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है उन स्थापनाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला मासिक विवरण।

1. प्रस्तावना:

(क) कोड संख्या तथा फैक्ट्री/स्थापना का नाम।

(ख) अधिकारी जिसने छूट प्रदान की है।

(ग) भविष्य निधि के लिये लेखा वर्ष।

2. कर्मचारी:

(क) पिछले मास के अंत तक कर्मचारियों की कुल संख्या।

(ख) माह के दौरान सेवा में आये कर्मचारियों की संख्या।

(ग) माह के दौरान नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या।

(घ) माह के अंत में कर्मचारियों की कुल संख्या।

स्थायी

अस्थायी

आकस्मिक

बदली

डेके:

डेकेदारों के श्रमिक

(ङ) सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों से भविष्य निधि सदस्यता से संबंधित घोषणा-पत्र, यदि कोई है, तो प्राप्त करें।

3. भविष्य निधि के अधिदाता:

पिछले मास के अंत तक अधिदाताओं की संख्या।

(ख) मास के दौरान छूट प्राप्त किए गए कर्मचारियों की संख्या और नए अभिदाताओं के रूप में नामांकन।

(ग) अन्य स्थापनाओं में विद्यमान उनकी भविष्य निधि सदस्यता को ध्यान में रखते हुए सदस्य बनाए गए व्यक्तियों की संख्या।

(क्या इन कर्मचारियों का अन्य स्थापनाओं में भविष्य निधि प्राप्त हो गया है)

(घ) मास के दौरान जिन अभिदाताओं ने सदस्यता बंद कर दी है उनकी संख्या।

(ङ) मास के अन्त में अभिदाताओं की संख्या।

4. वेतन, चालू अंशदान अर्थात् मास के दौरान अंशदान, वापसी आदि।

(क) भविष्य निधि अंशदान के लिए देय सकल वेतन की कुल राशि

(ख) अंशदान की दर।

(ग) भविष्य निधि देय का पूर्व बकाया।

(घ) चालू भविष्य निधि अंशदान।

(1) कर्मचारियों के वेतन से काटा गया उनका अंशदान।

(2) नियोक्ता का अंशदान।

(3) सदस्यों द्वारा कर्ज/अग्रिम राशि का पुनः भुगतान।

(घ) (ग) और (घ) का जोड़

(ङ) यदि कोई दायित्व ब्याज देता है तो क्या उसे अदा कर दिया गया है।

5. मास के दौरान अन्य आय

(क) निवेश पर ब्याज

रु.

(ख) परिपक्वता प्राप्ति

(1) राज्य/केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां

रु.

(2) राज्य/केन्द्रीय सरकार की गारंटी शुदा प्रतिभूतियां

रु.

(3) विशेष जमा स्कीम

रु.

(4) अन्य प्राप्त आय

रु.

(ग) जोड़

रु.

6. कुल प्राप्त आय (4 + 5)

रु.

7. अदायगी

रु.

(क) दावे

रु.

(ख) ऋण अग्रिम राशि

रु.

(ग) अन्य भविष्य निधि को अंतरण

रु.

(घ) अन्य अदायगी :

(अदायगी किस प्रकार की है)

रु.

(ङ) कुल (क) + (ख) + (ग) + (घ)

8. निवेश हेतु कुल उपलब्ध राशि

(मद 6 को जोड़ें और 7 को घटाएं)

9. निवेश का विवरण :

पिछले मास के अन्त में अगिवेशित बकाया राशि	मास के दौरान आबंटित राशि	कुल निवेश की गई राशि	अनिवेशित बकाया राशि	निवेश की तिथि अर्थात् प्रतिभूतियों की खरीदने की सही तिथि
---	--------------------------	----------------------	---------------------	--

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च)

(i) राज्य केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां

(ii) राज्य केन्द्रीय सरकार की गारंटीशुदा प्रतिभूतियां

(iii) विशेष जमा

(iv) अन्य

10. निरीक्षण प्रभार :

(क) बकाया वेयरशि, यदि कोई है

(ख) चालू मास के लिए देय राशि

(ग) मास के दौरान जमा की गई राशि

(घ) अदायगी की तिथि

(ङ) क्षतिपूर्ति हेतु दर में वसूल की गई राशि लेकिन उसे अदा नहीं किया गया।

11 31 मार्च को कुल निवेश (प्रत्येक वर्ष मार्च की विवरणी में प्रस्तुत किया जाना है) (अर्थात् आरंभ से निकाली गई राशि को घटाकर निवेश)।

(क) (i) राज्य/केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां।

(ii) राज्य/केन्द्रीय सरकार की गारंटीशुदा प्रतिभूतियां

(iii) डाकघर मियादी जमा :

(iv) राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र

(v) विशेष निक्षेप स्कीम :

(vi) अन्य (प्रतिभूतियों/निक्षेपों की प्रकृति को विनिर्दिष्ट किया जाए) :

(ख) सरकारी प्रामिमरी नोट्स, जिन्हें अभी स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में परिचालित किया जाना है, का अंकित मूल्य।

12. प्रतिभूतियों जिसके नाम खरीदी गई हैं। यदि ये भविष्य निधि न्याय के धारक के अतिरिक्त अन्य किसी के नाम से हैं तो उसकी राशि तथा उसके कारण बताएं।

टिप्पणी : निधियों के अनुसार प्रतिभूतियों को केवल न्याय/भविष्य निधिधारकों के नाम से खरीदा जाना होता है।

(ख) प्रतिभूतियों को किसकी अभिरक्षा में रखा गया है ? यदि बैंकर्स के पास है, तो क्या-उनसे सुरक्षित अभिरक्षा रसीदें आदि प्राप्त कर ली गई हैं।

13. भविष्य निधि लेखों की लेखा-परीक्षा :

(क) क्या लेखों की लेखा-परीक्षा करा ली गई है ? यदि हाँ, तो किस अवधि तक ? यदि नहीं, तो संक्षेप में उसके कारण बताएं ।

(ख) क्या लेखा-परीक्षित चुननपत्र क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ? यदि हाँ, तो किस अवधि तक ? यदि नहीं, तो संक्षेप में उसका कारण बताएं ।

14. अभिदाताओं को वार्षिक लेखा-विवरणियां :

(क) क्या अभिदाताओं को अव्यतन तिथि तक वार्षिक लेखा विवरणियां जारी कर दी गई हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो किस अवधि तक जारी की गई और न जारी किए जाने के कारण बताएं ।

(ग) अभी तक जारी न किए गए लेखों की संख्या (वर्षवार) ।

(घ) अभिदाताओं के खातों में जमा की गई ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर और ब्याज किस प्रकार निकाला गया ।

(च) ब्याज क्रेडिट करने की पद्धति अर्थात् क्या यह ग्रन्थ-शेष (ओपनिंग बैलेंस) पर, मासिक शेष पर या इति शेष (क्लोजिंग बैलेंस) पर है ।

15. भविष्य निधि के नियम :

(क) माह के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से किए गए संशोधन, यदि कोई हो, का विवरण ।

(ख) क्या भविष्य निधि नियम अद्यतन हैं ।

(ग) यदि नहीं, तो कौन से संशोधन किए जाने अभी शेष हैं ?

(घ) क्या भविष्य निधि नियम अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित हैं ।

(च) क्या भविष्य निधि नियमों की एक प्रति अभिदाताओं को उपलब्ध कराई गई है ।

16. स्थापना का निरीक्षण .

भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा किए गए पिछले निरीक्षण की तिथि ।

नियोजता या उसके प्राधिकृत अधि-

दिनांक : कारी के हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर

[स एम. 35012(14)/87-एम.एस.-II]

New Delhi, the 18th March, 1991

S.O. 936.—In pursuance of clause (a) Sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) read with sub-paragraph (2) of paragraph 27 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 3255, dated the 12th

November, 1963, the Central Government hereby directs that the employers in relation to the establishments whose employees have been granted exemption under paragraph 27 of the Employees' Provident Funds Scheme, shall submit a monthly return to the Regional Provident Fund Commissioner by the twenty fifth of the month following that to which it relates, in the proforma set out in the Schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Monthly return to be submitted by the establishments whose employees have been granted exemption under paragraph 27 of the Employees' Provident Fund Scheme.

1. INTRODUCTORY :

(a) Code No. and Name of the factory/establishment.

(b) Authority which granted the exemption

(c) Accounting year for the Provident Fund.

2. EMPLOYEES :

(a) Total No. of employees as at the end of the previous month.

(b) No. of employees who joined service during the month.

(c) No. of employees who left service during the month.

(d) Total No. of employees as at the end of month.

Permanent :

Temporary :

Casual :

Badli :

Contract :

Contractors: workers :

(e) Whether declaration relating to previous provident fund membership, if any, obtained from all new entrants to service.

3. SUBSCRIBERS TO THE PRIVATE PROVIDENT FUND:

(a) Number of subscribers as at the end of previous month.

(b) Number of employees granted exemption during the month and enrolled as new subscribers.

(c) Number enrolled in view of their subsisting Provident Fund membership in other establishments.

(Please also indicate whether provident fund of these employees has been received from other establishment).

(d) Number of subscribers who have ceased to be members during the month.

(e) Number of subscribers as at the end of the month.

4. WAGES, CURRENT CONTRIBUTIONS i.e. CONTRIBUTION DURING THE MONTH, REFUNDS ETC.

(a) Total amount of gross wages liable to provident fund contributions :

- (b) Rate of contributions: Rs.
 (c) Previous arrears of provident fund dues: Rs.
 (d) Current provident fund contributions: Rs.
 (i) Employees' share deducted from their wages : Rs.
 (ii) Employers share Rs.
 (iii) Repayment of loans/advances by the members Rs.
 (e) Total of (c) and (d) Rs.
 (f) Whether the penal interest due, if any, has been paid :

5. OTHER INCOME DURING THE MONTH

- (a) Interest on investments : Rs.
 (b) Maturity proceeds.
 (i) State/Central Govt. Securities. Rs.
 (ii) State/Central Govt. guaranteed securities. Rs.

- (iii) Special Deposit Scheme. Rs.
 (iv) Other receipts. Rs.
 (c) Total : Rs.

6. TOTAL RECEIPTS (4 + 5)

7. PAYMENTS

- (a) Claims Rs.
 (b) Loans/advances Rs.
 (c) Transfer to other provident funds Rs.
 (d) Other payments (nature of payments to be specified) Rs.
 (e) Total (a)+(b)+(c)+(d)

INVESTMENT

8. NET AMOUNT AVAILABLE FOR
(TOTAL ITEM 6 MINUS 7)

9. DETAILS OF INVESTMENTS

Balance lying uninvested at the end of the previous month	Amount allocated during the month	Total	Amount invested	Balance amount lying uninvested	Date of investment i.e. actual of date purchase of securities
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
(i) State/Central Govt. Securities					
(ii) State/Central Govt. guaranteed securities.					
(iii) Special Deposit					
(iv) Other					

10. INSPECTION CHARGES

- (a) Past dues, if any
 (b) Amount due for the month
 (c) Amount remitted during the month
 (d) Date of payment.
 (e) Amount of damages for belated remittance levied, but not paid.

11. TOTAL INVESTMENTS AS ON 31ST MARCH (TO BE FURNISHED IN THE RETURN FOR MARCH OF EACH YEAR) (i.e. INVESTMENT LESS REDEMPTION PROCEEDS FROM THE BEGINNING)

- (A) (i) State/Central Government securities :
 (ii) State/Central Government guaranteed securities :
 (iii) Post Office Time Deposits .
 (iv) National Small Savings Certificates :
 (v) Special Deposits Schemes :
 (iv) Others (nature of securities/deposits to be specified)
 (B) Face value of Government promissory notes yet to be converted as stock certificates.

12. (a) In whose names the securities have been purchased., If, the same are in the namt

of anyone other than the holder of the provident fund trust, amount thereof and the reasons thereunder.

Note :—Securities are required to be purchased only in the names of the Trust/holders of Provident Fund according to rules.

- (b) In whose custody the securities are kept? If with the Bankers, whether safe custody receipts etc. have been obtained from them.

13. AUDIT OF PROVIDENT FUND ACCOUNTS :

- (a) Have the accounts been audited ? If so, up to what period ? If not, brief reasons therefor.

- (b) Have the audited balance sheets been submitted to the Regional Provident Fund Commissioner?

If so, upto what period ?

If not, brief reasons therefor.

14. Annual Statements of Accounts to Subscribers :

- (a) Have the subscribers been issued the annual statements of accounts upto date?

- (b) If not, period upto which issued and brief reasons for non-issue.
- (c) Number of accounts not yet issued (Year-wise)
- (d) Rate of interest credited to the subscribers' account, year, interest rate and how the rate was arrived at.
- (d) Method of crediting interest i.e. whether it is on opening balance, monthly balance or closing balance.

15. Rules of the Provident Fund :

- (a) Details of amendment, if any, carried out during the month with the approval of the Regional Provident Fund Commissioner.
- (b) Are the Provident Fund Rules upto date.
- (c) If not, what are the amendments yet to be carried out?
- (d) Whether the Provident Fund Rules are printed in English as well as in regional language.
- (e) Whether a copy of the provident fund rules has been supplied to the subscribers.

16. INSPECTION OF THE ESTABLISHMENT
Date of last inspection by the provident Fund Inspector.

Dated :

Signature with Official
Seal of the Employer or
his Authorised Official.

[No. S-35012(14)/87-SS-II]

का. आ. 937—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27-क क उप पैरा (2) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उन स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता, जिनके कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 27-क के अंतर्गत एक वर्ग के रूप में छूट मंजूर की गई है, भारत सरकार (पूर्वनाम) श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) का. आ. स. 3469 दिनांक 22 अगस्त, 1983 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, की अधिसूचना में निर्धारित प्रोफार्मा में यह मासिक रिटर्न जिस महीने में संबंधित है उसके अनुगामी महीने की 25 तारीख तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेगा।

[स एस-35012/14/87-एस.एस.-II]

S.O. 937.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), read with sub-paragraph (2) of paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, the Central Government hereby directs that the employers in relation to the establishments whose

employees have been granted exemption as a class under paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme 1952 shall submit a monthly return to the Regional Provident Fund Commissioner by the twenty fifth of the month following that to which it relates, in the proforma prescribed in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) S.O. No. 3469, dated the 22nd August, 1983, as amended from time to time.

[No S-35012/14/87-SS.II]

नई दिल्ली 19 मार्च 1991

का आ 938—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 की 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के का आ स 214 दिनांक 8 जनवरी, 1988 के अधिक्रमण में उक्त अधिनियम प्रवर्तन से मैमर्स गोवा मीट कपलेक्स लि., पोडा, गोवा नियुक्त नियमित कर्मचारियों को 18 मई 1982 में 30 मितम्बर, 1991 तक कि जिसमें यह दिनांक भी सम्मिलित है कि अवधि के लिए छूट प्रदान करनी है।

2 पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात् —

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाये जाएंगे
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व सदन अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते हैं,
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की वाकत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसने इसके पश्चात् "उक्त अवधि" हो गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्राहण में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की वाकत देती थी,
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निम्न प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

- (1) धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन, उक्त अधिधि की वाचत दी गई किसी नियमों को विशिष्टियों को गन्थापित करने के प्रयोजनार्थ,
- (2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख धन अधिधि के लिए रखे गये थे या नहीं, या
- (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक आग दिग्गए, उन फायदों को, जिसके प्रतिकर वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या
- (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अधिधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा :—

- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक अपक्षा करने कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है,
- (ग) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिधोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, वहीयों और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे, जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक की, उसके अधिकारों या सेवा की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षण या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का गन्तिमय कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या
- (व) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज को नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[ग.मा.प.ग-39014/7/89-ग.प.प.म-1]

प. के भट्टराई, "गवर नॉचर"

स्पष्टीकरण आपन

इस मामले में छूट को भूलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पत्र बेरी से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 19th March, 1991

S.O. 938.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. SO 214 dated 8-1-1988 the Central Government hereby exempts the regular employees of The Goa Meat Complex Limited, Ponda-GOIA. from the operation of the said Act for a period with effect from 18th May, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1991.

The above exemption is subject to the following conditions namely :—

- (1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees.
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates.
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded,
- (4) The employer of the said factory/establishment shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), 'such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations 1950.
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purpose of :—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of the section 44 for the said period, or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force relation to the said factory to empower to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine accounts books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory establishment, office or other premises.

[No. S-38014/7/89 SS-I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely

